जनहितैषी

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक: 81 दिनांक:24-07-2024 बुधवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हैं। केंद्र सरकार ने अपना बजट 9 बिंदुओं पर केंद्रित किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया और कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां बजट पेश किया...

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट... हर वर्ग के लिए खोला पिटारा

नई दिल्ली(ईएमएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हैं। केंद्र सरकार ने अपना बजट 9 बिंदुओं पर केंद्रीत किया है। ये हैं-खेती में प्रोडक्टिविटी, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, रोजगार और स्किल, सामाजिक न्याय, निर्माण और सेवा, शहरी विकास, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार का सुधार।

खेती-किसानी के लिए बजट में

बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है. इस बजट में खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है. इससे पहले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50प्रतिशत मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ. इस बार झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया जाएगा. झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड द्वारा फंडिंग की जाएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है. किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएगी. देश भर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन, क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10 हजार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संस्थान केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि के उत्पादन में उत्पादकता और लचीलापन लाने पर जोर है. फसलों की नई किस्मों को जारी करने में मदद की जाएगी. अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी. दलहन और तिलहन के लिए मिशन शुरू होगा. सरकार उनके उत्पादन और मार्केटिंग को मजबूत करेगी.

वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा, इस बार नेचुरल फार्मिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, 2 साल में 1 करोड़ किसानों ने नेचुरल फार्मिंग को अपनाया है. किसानों के लिए 1 हजार बायो रिसोर्स सेंटर बनाए गए. दलहन-तिलहन मिशन पर जोर दिया जा रहा है. इस साल सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा. 32 फसलों के लिए 109 वैराइटी लॉन्च की जाएगी. इसके साथ ही खेती के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे. 6 करोड़ किसानों के जमीन को रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. 5 राज्यों में किसान क्रडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा. 400 जिलों में डिडिटल खरीफ फसल सर्वे किया जाएगा. इसके साथ ही दालों, ऑल सीड्स विस्तार पर मिशन लॉन्च किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है. केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है. इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा. इस योजना में बिहार के लिए कई सौगात हैं. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा. सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इस मॉडल को विकास भी विरासत भी का नाम दिया जाएगा. इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी पर भी बढ़ाया जाएगा. इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा. इसके लिए 26000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

राज्य खनिज संपदा वाली जमीन पर टैक्स लगा सकते हैं? - फैसला 25 जुलाई को

नई दिल्ली (ईएमएस)। क्या राज्य खनिज संपदा वाली जमीन पर टैक्स लगा सकते हैं या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ 25 जुलाई को इस पर फैसला सुनाएगी। यह मामला पिछले 25 साल से कोर्ट में लंबित है।

देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर गंभीर असर पड़ सकता है।

अदालत को टैक्स को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की महत्वपूर्ण व्याख्या करनी है। 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। 8 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।

दरअसल राज्यों पर असर डालने वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के संविधान पीठ ने सुनवाई की है। राज्यों के टैक्स लगाने के अधिकार से जुड़ी 85 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। ये मामला 2011 में 9 जजों की बेंच को भेजा गया था। क्योंकि इस मामले में पांच जजों और सात जजों के संविधान पीठ के फैसलों के बीच विरोधाभास था

तीन जजों की बेंच ने 9 जजों की बेंच को भेजे जाने के लिए 11 सवाल तैयार किए थे। इनमें महत्वपूर्ण टैक्स कानून के सवाल शामिल हैं जैसे कि क्या रॉयल्टी को टैक्स के समान माना जा सकता है। क्या राज्य विधानमंडल भूमि पर टैक्स लगाते समय भूमि की उपज के मूल्य के आधार पर टैक्स का उपाय अपना सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी नीट-यूजी की परीक्षा

नई दिल्ली(ईएमएस)। नीट केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि फिलहाल, हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है जिसके लिए कोई डेट जारी नहीं की है।

नीट केस में सीजेआई की बेंच के सामने मंगलवार को पांचवीं सुनवाई हुई। सीजेआई ने कहा- हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।

पटना और हजारीबाग में हुआ है पेपर लीक

सीजेआई ने कहा, पटना और हजारीबाग में लीक होने पर कोई विवाद नहीं है। सीबीआई के खुलासे से पता चलता है कि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन पटना और हजारीबाग के अभ्यर्थी लीक से लाभान्वित हुए प्रतीत होते हैं।

आदेश सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत कमियां थीं। वर्तमान जैसे मामले में, यह जरूरी है कि इस विवाद को तत्काल निश्चितता और अंतिमता प्रदान की जाए, क्योंकि इससे 23 लाख से अधिक छात्रों का करियर प्रभावित होता है।

40 से अधिक याचिकाओं पर चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। शीर्ष कोर्ट ने आज भी मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि यह सच है कि पेपर लीक हुआ है, इसपर कोई विवाद नहीं है। नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी। सीजेआई ने आदेश की शुरुआत में मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें दर्ज कीं। उन्होंने कहा कि 1,08,000 सीटों के लिए 24 लाख छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि 50 प्रतिशत कट ऑफ का प्रतिशत दर्शाता है। परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनके कुल अंक 720 होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है। यह प्रस्तुत किया गया कि पेपरलीक प्रकृति में प्रणालीगत था और संरचनात्मक कमियों के साथ मिलकर कार्रवाई का एकमात्र स्वीकार्य तरीका री-टेस्ट करना होगा। लेकिन, परीक्षा की पवित्रता भंग होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

बजट पर मायावती, अच्छे दिन नहीं मायूस करने वाला , कांग्रेस और सपा ने बताया निराशाजनक बजट

लखनऊ (ईएमएस)। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश हुआ। इस पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख और पूर्व सीएम मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, संसद में बुधवार को पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्नासेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। उन्होंने लिखा, देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन और 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव।

इसके साथ ही बसपा प्रमुख ने लिखा, देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल-भुलैया वाला न हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के मौके, जेब में खर्च के लिए पैसे/आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति-जरूरी। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे।

वहीं सपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि मोदी सरकार ने जो आज बजट पेश किया है, इस बजट ने गरीब, किसान और नौजवानों को निराश किया है। इसमें बड़े लोगों को फायदा है। गरीबों और छोटे तबकों की उम्मीदों पर मोदी सरकार ने पानी फेरा है। यूपी की उपेक्षा लगातार 10 सालों से हो रही है। यही यूपी ने इन्हें सबसे ज्यादा दो बार सांसद दिया। खुद पीएम यहीं से चुन कर जाते हैं।

दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट सिर्फ हवा-हवाई और किताबी है। बजट में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों की घोर उपेक्षा की गई है। शायद भाजपा 2024 में चुनाव में जो सीटों में कमी हुई हैं, इसकारण वह युवाओं और आम आदमी से अपनी कुंठा बजट में निकाल रही है। बजट में किसी भी वर्ग को राहत नहीं दी गई है।

कर्नाटक की यूटर्न सरकार.....एक सप्ताह में दूसरे बिल पर पलटी

नई दिल्ली (ईएमएस)। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार फिर चर्चा में है। एक ओर में दूसरी बार सिद्धारमैया सरकार को अपने ही फैसले से यूटर्न लेता देखा गया है। आईटी कर्मचारियों के लिए रोज 14 घंटे काम के नियम वाले बिल पर सिद्धारमैया सरकार ने यूटर्न ले लिया है। सरकार में श्रम मंत्री संतोष लाड ने सफाई देकर कहा, टेक सेक्टर वालों से और ज्यादा घंटे काम लेने के लिए उन पर कानून बनाने के संबंध में आईटी इंडस्ट्री का दबाव है, लेकिन वे इस मामले का मूल्यांकन कर रहे हैं। मंत्री लाड का कहना था कि सरकार अभी भी विधेयक को परख रही है, जिससे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हर रोज 14 घंटे काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

हालांकि, बीजेपी विधेयक का लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इस मसले पर चर्चा की जरूरत है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस मामले में एकतरफा फैसला नहीं ले सकती है। आईटी क्षेत्र के कर्मचारी और ट्रेड यूनियनों ने पहले ही इस कदम का विरोध कर अमानवीय बताया है। विरोध के चलते सरकार इस बिल पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री से अपील है कि बेंगलुरु ग्लोबल आईटी हब है। ये फैसला सभी को लेकर भरोसे में लेकर किया जाए।

दरअसल, मंत्री लाड का कहना था कि आईटी इंडस्ट्री के दबाव के कारण ही ये बिल हमारे पास आया है। आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे खुद प्रस्ताव को लेकर नहीं आए हैं। उद्योगपति हम पर 14 घंटे कार्य दिवस का विधेयक पारित करने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि, ये बिल हमारे पास है और हम (श्रम विभाग) इसका मूल्यांकन कर रहे हैं. आईटी प्रमुख और बड़ी कंपनियों के मालिकों को इस पर चर्चा करने की जरूरत है।

नए प्रस्ताव में कहा गया है कि आईटी/आईटीईएस/बीपीओ सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी को एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति होगी। प्रति सप्ताह 70 घंटे किया जा सकता है। हालांकि, लगातार तीन महीनों में 125 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि इसमें इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन कर्नाटक राज्य आईटी/आईटीईएस कर्मचारी संघ (केआईटीयू) के अनुसार नया संशोधन विधेयक हर रोज 14 घंटे काम करने की अनुमति देता है। ये मौजूदा कानून को पूरी तरह से बदल देगा। अभी ओवरटाइम सहित प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे काम की अनुमति है। केआईटीयू का कहना है कि कानून में संशोधन का प्रस्ताव उद्योग के विभिन्न हितधारकों के साथ श्रम विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रस्तुत किया गया था। यूनियन प्रतिनिधियों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राज्य के श्रम मंत्री संतोष लाड, श्रम विभाग के प्रधान सचिव मोहम्मद मोहसिन से मुलाकात की।

मोदी सरकार 3.0 के बजट पर खरगे........मोदी सरकार बचाओ

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की तरक्की वाला नहीं, बल्कि 'मोदी सरकार बचाओ बजट पेश किया है।

उन्होंने दावा किया कि यह 'नकलची बजट है, इसमें सरकार कांग्रेस के 'न्याय के एजेंडे की ठीक तरह से नकल नहीं कर सकी है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने पोस्ट किया, कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट ! मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है, ताकि राजग बची रहे। यह देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है।

उन्होंने कहा, ''10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुई हैं, जो सालाना दो करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। किसानों के लिए केवल सतही बातें हुई हैं। डेढ़ गुना एमएसपी और आय दोगुना करना, सब चुनावी धोखेबाजी निकली। ग्रामीण वेतन (आय) को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं है।

दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, माध्यम वर्ग और गांव-गरीब लोगों के लिए कोई भी क्रांतिकारी योजना नहीं है, जैसी कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने लागू की थी। राहुल गांधी ने बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है।

कल संसद परिसर में बजट के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन

नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, युवाओं, नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़े एलान किए गए हैं। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा।

विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा कल यानी बुधवार को बजट के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि विपक्ष ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बुधवार को संसद परिसर में बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में, कई जगह भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली,(ईएमएस)। देश के कई राज्यों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। कई राज्य इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ओडिशा और गोवा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली-एनसीआर में उमस के बीच बीते दिन हल्की बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया है। मौसम विभाग ने बुधवार तक दिल्ली में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी राजस्थान में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में हल्की या भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब दिल्ली पूर्वी यूपी, तमिलनाडु और रायलसीमा में हल्की बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ओडिशा के तटीय क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ गया है। अब निचले स्तर के रूप में आंतरिक ओडिशा पर स्थित है। वहीं औसत समुद्र तल पर मानसून ट्रफ आंतरिक ओडिशा के ऊपर चिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र जैसलमेर, कोटा, गुना, जबलपुर और रायपुर से होकर गुजरती है और वहां से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी तक जाती है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं राजस्थान के मध्य भाग, गुजरात के कच्छ क्षेत्र पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है।

यूपी-बिहार में हल्की तो पंजाब-हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून ब्रेक के बाद यूपी का मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया। अगले कुछ घंटो में कई जिलों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को बरेली, आगरा और फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, गोरखपुर और मेरठ में बारिश हो सकती है। वहीं, वाराणसी, अयोध्या और रायबरेली में बादल छा सकते हैं।

मानसून कमजोर होने से बिहार में बारिश कम हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को पटना समेत 20 जिलों में गरज के साथ हल्की तो कहीं पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है यहां येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हरियाणा में 22 दिनों बाद मौसम फिर मेहरबान हो गया है।

हिमाचल में बनी दस दवाएं फेल

देहरादून (ईएमएस)। उत्तराखंड में बनी पांच दवाओं के सैंपल जांच में सबस्टैंडर्ड मिले हैं। इसमें दर्द निवारक और गैस की गोलियां शामिल हैं। केंद्रीय दवा मानक कंट्रोल संस्थान की ओर से ड्रग अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद राज्य के ड्रग कंट्रोलर ने संबधित फार्मा कंपनियों को इन दवाओं का उत्पादन रोकने के आदेश दिया हैं।

देश में बनी दवाओं के सैंपल विदेश में फेल होने के बाद से केंद्रीय दवा मानक कंट्रोल संस्थान हर महीने देशभर में बनी दवाओं की जांच कर रहा है।

कनाडा में फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया....भारत विरोधी टिप्पणियां लिखी गई

कनाडा (ईएमएस)। कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। खालिस्तान समर्थकों पर कनाडा में एक्शन ना होकर उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में कनाडा के एडमोंटन में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी टिप्पणियां लिख दी गई। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने बताया कि बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। साथ ही कहा कि ग्रैफिटी के द्वारा भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य पर भी हमला किया गया।

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने पोस्ट में लिखा, कनाडा के एडमोंटन में मंदिर आज सुबह एक और हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। मंदिर पर कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ हिंदू सदस्यों में से एक के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। हम इस घटना की निंदा करते हैं जो पिछले कई हमलों का ही हिस्सा है जिनमें से ज्यादातर के लिए खालिस्तान समर्थक दोषी हैं।

सांसद आर्य ने कहा है कि कनाडा में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आर्य ने कहा, एडमॉन्टन में स्वामीनारायण मंदिर में फिर से तोड़फोड़ की गई है। पिछले कुछ सालों में ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के दूसरे जगहों पर हिंदू मंदिरों को ग्राफिटी के जरिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

सांसद चंद्र आर्य ने कहा, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं, खालिस्तानी चरमपंथी हिंसा फैलाने के बावजूद आसानी से बच जाते हैं। फिर से मैं इस रिकॉर्ड पर रखूंगा। हिंदू कनाडाई इससे चिंतित हैं। मैं फिर से कनाडा की कानूनी एजेंसियों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की गुजारिश करता हूं, इससे पहले कि ये बयानबाजी लोगों के खिलाफ शारीरिक हिंसा में तब्दील हो जाए।

नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर 'स्पष्ट और दृढ़', भारतीय क्षेत्रों पर दावा, पीएम बनते ही ओली ने उठाया सीमा विवाद का मुद्दा

काठमांडू,(ईएमएस)। नेपाल के नवनियुक्त पीएम के.पी.ओली शर्मा ने कहा कि भारत के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों को कूटनीतिक तंत्र के जरिए हल करने के लिए तैयार है और काठमांडू अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में 'स्पष्ट और दृढ़' है। प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने के एक दिन बाद सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए ओली ने कहा कि सरकार इस बात पर दृढ़ और स्पष्ट है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख समेत महाकाली नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र नेपाल के हैं।

ओली ने कहा कि संघीय संसद और नेपाल सरकार का रुख देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर स्पष्ट और दृढ़ है। उन्होंने कहा कि नेपाल ने एक नया मानचित्र अपनाया है, जिसे 2017 में संविधान में दूसरे संशोधन के जरिए से शामिल किया गया है और इसके अनुलग्नक तीन में उल्लेख किया गया है और हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में अभूतपूर्व राष्ट्रीय सहमति बनी है। ओली ने 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उच्चस्तरीय यात्राओं के दौरान हुई मुलाकातों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तंत्र के जरिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी है। ओली ने कहा कि 4 जनवरी को आयोजित नेपाल-भारत विदेश मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग की सातवीं बैठक के दौरान नेपाल-भारत सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी और नेपाल-भारत सीमा के शेष हिस्सों पर लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

वित्त मंत्री ने चुपके से खत्म कर दिया इंडेक्सेशन बेनिफिट

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने चुपके से संपत्ति की बिक्री पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म करने की घोषणा कर दी है। अब प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग अपनी खरीद कीमत नहीं बढ़ा पाएंगे और अपने पूंजीगत लाभ को कम नहीं कर पाएंगे। अब तक की व्यवस्था में प्रॉपर्टी की सेल से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के भीतर 20 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता था। अब प्रॉपर्टी की सेल पर पूंजीगत लाभ के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना 12.5 प्रतिशत का नया एलटीसीजी टैक्स रेट लागू होगा।

मान लीजिए आपने वित्त वर्ष 2002-2003 में 25 लाख रुपये में एक प्रॉपर्टी खरीदी। आप वित्त वर्ष 2023-2024 में एक करोड़ रुपये में उस प्रॉपर्टी बेच देते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार 25 लाख रुपये की खरीद कीमत को इनकम टैक्स द्वारा नोटिफाई किए गए सीआईआई नंबरों के साथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन नया नियम लागू होने के बाद खरीद मूल्य को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। टैक्सपेयर को बिक्री मूल्य से खरीद मूल्य को कम करके पूंजीगत लाभ की गणना करनी होगी। सीतारमण ने कहा कि इससे टैक्सपेयर और टैक्स अधिकारियों के लिए कैपिटल गेन की गणना करना आसान होगा।

सीआईआई क्या है

हर वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स विभाग इंडेक्सेशन बेनिफिट की गणना में उपयोग किए जाने के लिए एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (सीआईआई) प्रकाशित करता है। इसका यूज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की इन्फ्लेशन-एडजस्टेड कॉस्ट की गणना करने के लिए किया जाता है। टैक्सेबल कैपिटल गेन का निर्धारण करने के लिए एसेट की सेल वैल्यू से इन्फ्लेशन-एडजस्टेड एक्विजिशन कॉस्ट को हटा दिया जाता है। हालांकि, इंडेक्सेशन बेनिफिट केवल खास तरह की एसेट्स पर उपलब्ध है।

केंद्र ने संघ से हटाया प्रतिबंध......राजस्थान की बारी का इंतजार

जयपुर (ईएमएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में अपने कार्मिकों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगी रोक हटा दी है। 58 साल पहले वर्ष 1966 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पर संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाया है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 1981 में राज्य कर्मचारियों पर संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था जो आज तक जारी है।

कई यूजर केंद्र के इस फैसले को सही बता रहे हैं, कई लोग विरोध में उतर आए हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि संघ की गतिविधियां देश विरोधी थी। इसकारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ प्रतिबंध लगाया था। दोनों ही पक्षों की ओर से अपने अपने तर्क देने का सिलसिला जारी है।

संघ सहित तीन संगठनों पर राज्य सरकार ने 43 साल पहले वर्ष 1981 में प्रतिबंध लगाया था जो आज तक जारी है। तत्कालीन मुख्य सचिव मदन मोहन किशन वाली 18 मार्च 1981 में आरएसएस, जमात ए इस्लामी और आनंद मार्ग संगठन से संबंद्धता रखने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी इन तीनों संगठनों के ना तो सदस्य बन सकते और ना ही उनकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

राजस्थान में भाजपा की सरकार पांच बार बन चुकी है और 18 साल तक भाजपा सत्ता में रह चुकी है। वर्ष 1989 से 1998 तक भैरोसिंह सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2003 से 2008 और वर्ष 2013 से 2018 तक प्रदेश में भाजपा की सरकार रही और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहीं। वर्तमान में भाजपा पांचवीं बार सत्ता में है और भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद भी आरएसएस में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध को हटाया नहीं गया। तीनों संगठनों पर लगा प्रतिबंध पूर्व की भांति जारी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नेमप्लेट हटाने से डर रहे कारोबारी

मुजफ्फरनगर (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर होटल से लेकर ठेले वालों के लिए नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम आदेश के बावजूद अभी दुकानदार नेमप्लेट हटाने से डर रहे हैं। इसके लिए अभी भी प्रशासन की हरी झंडी का इंतजार हो रहा है।

मुजफ्फरनगर के दुकानदार ने बताया कि वे अभी नेमप्लेट हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण की तरफ से निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक अन्य दुकानदार ने कहा कि दस दिन पहले तक हर रोज का खर्च 15 हजार रुपये था। लेकिन पिछले 24 घंटे में केवल 4 हजार की कमाई हुई है। हालांकि चाय और खाने में पूरी सतर्कता बरतते हैं, लेकिन लोग नाम पढ़कर ही आगे बढ़ जाते हैं।

इन लोगों का कहना है कि ये बोर्ड परमानेंट के लिए हटने चाहिए। इससे दुकानदारी घट गई थी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। हां जी हमने बोर्ड हटा दिए हैं, देखिए यह भेदभाव था यह बोर्ड परमानेंट हटने चाहिए। इससे कारोबार पर बहुत गलत असर पड़ रहा था, जिससे दुकानदारी घट गई थी।

जन हितैषी

मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट, मोदी गारंटी की तरह?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार लोकसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट में कई लोक-लुभावन घोषणाएं की गई हैं। घोषणाओं के लिए स्पष्ट बजट नहीं दिया गया है। बेरोजगारों, युवाओं और महिलाओं के लिए जिस तरीके की योजनाएं पेश की गई हैं, उनमें कोई स्पष्टता नहीं है। बजट आवंटन भी स्पष्ट नहीं है। बजट में गरीब महिलाएं, युवा, बेरोजगार और किसानों की योजनाओं का बढ़-चढ़कर गुणगान किया गया है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दिया गया है। अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। युवाओं के रोजगार और रोजगार मूलक प्रशिक्षण के लिए स्टाइफंड देने की व्यवस्था बजट में की गई है। मध्यवर्ग के लिए टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय पर पांच फीसदी, 7 से 10 लाख की आय पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए की आय पर 15 फ़ीसदी, 12 से 15 लाख रुपए की आय पर 20 फ़ीसदी, 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फ़ीसदी आयकर का स्लिलेब बनाया गया है। किसानों के लिए दाल और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 5 वर्षों में 4.01 करोड़ युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की योजना, शिक्षा रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए देने की घोषणा की गई है। बेरोजगार युवाओं को इंडस्ट्री में प्रशिक्षण मिले उन्हें 15000 रूपये प्रतिमाह की सहायता राशि, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। 30 लाख युवाओं को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 3000 रूपये प्रति हितग्राही 2 साल तक देने, शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़, एक करोड़ घरों को फ्री बिजली, आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने के लिए 63000 करोड़ रुपए की सहायता, ग्रामीण अंचलों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने के लिए 11500 करोड़ की वित्तीय मदद देने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। 2024 25 के बजट में मोबाइल फोन, चार्जर, आयातित सोने-चांदी, कैंसर की दवाएं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जूते-चप्पल, कपड़े, कॉपर,लोहे का स्क्रेप तथा महत्वपूर्ण खनिज के शुल्क को घटाया गया है। यह भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस बजट में जो चीजें महंगी होगी। उसमें प्लास्टिक का सामान, सिगरेट, पेट्रोकेमिकल तथा अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है। उसमें पारदर्शिता का अभाव है। चुनावी घोषणा की तरह इस बजट में घोषणाएं ज्यादा हैं। बजट में उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, इसका खुलासा नहीं है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसमें भी कोई ऐसी स्पष्टता नहीं है, जिसमें यह कहा जा सके कि उन्हें एक निश्चित समय पर कोई बड़ी आर्थिक सहायता मिलने जा रही है। वर्ष 2024 25 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है। वह एक तरह से निराश करने वाला बजट है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है, लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी गारंटी मतदाताओं को दी थी। इसी तरह से बजट में भी वित्तमंत्री ने गारंटी दी है। यह गारंटी किस तरह और कब पूरी होगी, इसके बारे में बजट में कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए है। पिछले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केंद्र सरकार ने बजट से जो प्रावधान किए थे। वह राशि उन योजनाओं के लिए जारी नहीं हो पाई। जिसके कारण सैकड़ों प्रोजेक्ट कई वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। इनकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा, इसका उल्लेख भी बजट में नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने कई विभागों के बजट को पिछले वर्ष की तुलना में कम कर दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 35 फ़ीसदी किया गया है। एक तरह से यह बजट कॉरपोरेट कंपनियों को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने में मददगार साबित होगा। आम लोगों को इस बजट में कई योजनाओं की घोषणा जरूर की गई है। बजट में उसके लिये स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बजट भाषण में यह भरोसा जरूर दिलाया गया है, मांग के अनुरूप योजनाओं में राशि आवंटित की जाएगी। बिहार और आंध्र प्रदेश को जरूर इस बजट का लाभ मिला है। यह मोदी सरकार की मजबूरी थी। अन्य राज्यों की उपेक्षा हुई है।

महानगरों में बढ़ता जानलेवा प्रदूषण गंभीर चुनौती

चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी चर्चित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका लासेंट के हाल के अध्ययन में वायु प्रदूषण की बढ़ती विनाशकारी स्थितियों के आंकड़े न केवल चौंकाने वाले है बल्कि अत्यंत चिन्तातनक है। भारत के दस बड़े शहरों में हर दिन होने वाली मौतों में सात फीसदी से अधिक का मुख्य कारण हवा में व्याप्त प्रदूषण है। वहीं दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा साढ़े ग्यारह प्रतिशत है। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण के रूप में पसर रही मौत के लिये सरकार एवं उनसे संबंधित एजेंसियों की लापरवाही एवं कोताही शर्मनाक है, क्योंकि सरकार द्वारा 131 शहरों को आवंटित धनराशि का महज 60 फीसदी ही खर्च किया जाता है। गंभीर से गंभीरतर होती वायु प्रदूषण की स्थितियों के बावजूद समस्या के समाधान में कोताही चिन्ता में डाल रही है एवं आम जनजीवन के स्वास्थ्य को चौपट कर रही है। महानगरों में प्रदूषण का ऐसा विकराल जाल है जिसमें मनुष्य सहित सारे जीव-जंतु फंसकर छटपटा रहे हैं, जीवन सांसों पर छाये संकट से जूझ रहे हैं।

केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण एवं हवा में घुलते जहरीले तत्वों की चुनौती के मुकाबले के लिये राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की घोषणा 2019 में की थी। जिसका मकसद था कि खराब हवा के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार की कोशिश थी कि देश के चुनिंदा एक सौ तीस शहरों में वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2024 तक घातक धूल कणों की उपस्थिति को बीस से तीस फीसदी कम किया जा सके। लेकिन विडम्बना है कि तय लक्ष्य हासिल नहीं हो सके। महानगरों-नगरों को रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हालांकि लोगों को सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है, एंटीडस्ट अभियान को निरन्तर जीवन का हिस्सा बनाना होगा। लोगों को खुद भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी। लोगों को खुली जगह में कूड़ा नहीं फैंकना चाहिए और न ही उसे जलाया जाए। वाहनों का प्रदूषण लेवल चैक करना चाहिए। कोशिश करें कि हम निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली पटाखे जलाने की भौतिकतावादी मानसिकता को विराम देना जरूरी है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की वैश्विक अभिधारणा को मूर्त रूप देने के लिये इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की दिशा में गत दो-तीन साल में कई पायदान हम ऊपर चढ़े हैं, एक सकारात्मक वातावरण बना। लेकिन पटाखों से ज्यादा खतरनाक हैं पराली का प्रदूषण। पराली आज एक राजनीतिक प्रदूषण बन चुका है। दिल्ली एवं पंजाब में एक ही दल ही सरकारें है, दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार समाधान देती।

प्रदूषण से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा-सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता। क्षण-क्षण अग्नि-परीक्षा देता है। पर हां! अग्नि परीक्षा से कोई अपने शरीर पर फूस लपेट कर नहीं निकल सकता। इसके लिये शहरों में वृक्षारोपण करके हरियाली का दायरा बढ़ाना, कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, इलेक्ट्रानिक वाहनों को प्रोत्साहन तथा इन वाहनों के लिये चार्जिंग स्टेशन बनाने जैसे प्रयास करने के सुझावों का क्रियान्वित करने की अपेक्षा है, इसके लिये जो कार्यक्रम प्रदूषण से ग्रस्त चुनिंदा शहरों में चलाया जाना था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। जिससे समस्या उग्र से उग्रतर होती जा रही है। इसी कारण देश के अधिकांश शहर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। लेकिन स्थानीय निकायों व प्रशासन ने संकट की गंभीरता को नहीं समझा। इस दिशा में अपेक्षित सक्रियता नजर नहीं आई। प्रश्न है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस महासंकट से जूझ रहे महानगरों को कोई समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती? सरकारें एवं राजनेता एक दूसरे पर जिम्मेदारी ठहराने की बजाय समाधान के लिये तत्पर क्यों नहीं होते? प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रही है?

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये सक्रिय है, केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये करीब साढ़े दस हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। लेकिन विडम्बना है कि पर्याप्त फण्ड होने के बावजूद सिर्फ साठ फीसदी राशि ही इस मकसद के लिये खर्च की गई। वहीं सत्ताईस शहरों ने बजट का तीस फीसदी ही खर्च किया। कुछ शहरों ने तो इस मकसद के लिये आवंटित धन का बिल्कुल उपयोग नहीं किया। कैसे समस्या से मुक्ति मिलेगी? जीवाश्म ईंधन के उपयोग, सड़कों पर निरंतर बढ़ते पेट्रोल-डीजल वाहन, सार्वजनिक यातायात की बदहाली व कचरे का ठीक से निस्तारण न होने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लक्ष्य हासिल करना जटिल होता जा रहा है। अब समस्या की विकरालता को देखते हुए केंद्र सरकार इस दिशा में नये सिरे से गंभीरता से पहल कर रही है, जिससे प्रदूषित शहरों को दी जाने वाली राशि का यथा समय अधिकतम उपयोग हो सके। पराली की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1347 करोड़ रुपये और उपकरण दिए गए। अगर इस पर राजनीति करने की जगह ईमानदारी से काम होता तो प्रदूषण को कम करने की दिशा में हम कुछ कदम बढ़े होते।

वायु प्रदूषण एक जाना-पहचाना पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरा है। हम जानते हैं कि हम क्या देख रहे हैं जब भूरे रंग की धुंध शहर के ऊपर छा जाती है, व्यस्त राजमार्ग पर धुआँ निकलता है या धुएँ के ढेर से धुआँ निकलता है। वायु प्रदूषण मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों स्त्रोतों से उत्पन्न खतरनाक पदार्थों का मिश्रण है। वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, घरों को वातानुकूलित करने के लिए ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस, एसी का उपयोग, विनिर्माण और बिजली उत्पादन के उप-उत्पाद, विशेष रूप से कोयला-ईंधन वाले बिजली संयंत्र, और रासायनिक उत्पादन से निकलने वाले धुएं मानव निर्मित वायु प्रदूषण के प्राथमिक स्त्रोत हैं। बढ़ता प्रदूषण वैश्विक स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक बड़ा खतरा है। वायु प्रदूषण सभी रूपों में, हर साल दुनिया भर में 6.5 मिलियन से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है यह संख्या पिछले दो दशकों में बढ़ी है। भारत के महानगरों में यह अधिक विकराल होती जा रही है। उच्च वायु प्रदूषण से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में कैंसर, हृदय रोग, श्वसन रोग, मधुमेह, मोटापा, तथा प्रजनन, तंत्रिका संबंधी और प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी विकार शामिल हैं।

वायु प्रदूषण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक होने लगती है। महानगरों की हवा में उच्च सांद्रता है, जो बच्चों को सांस की बीमारी और हृदय रोगों की तरफ धकेल रही है। शोध एवं अध्ययन में यह भी पाया गया है कि दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले 75.4 फीसदी बच्चों को घुटन महसूस होती है। 24.2 फीसदी बच्चों की आंखों में खुजली की शिकायत होती है। सर्दियों में बच्चों को खांसी की शिकायत भी होती है। बुजुर्गों का स्वास्थ्य तो बहुत ज्यादा प्रभावित होता ही है। हवा में कैडमियम और आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कैंसर, गुर्दे की समस्या और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। 300 से अधिक एक्यूआइ वाले शहरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी सहित अनेक महानगर क्षेत्र में रहने वाले सांस के रूप में जहर खींचने को क्यों विवश है, इसके कारणों पर इतनी बार चर्चा हो चुकी है कि उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं। निस्संदेह, राज्यों के शासन व स्थानीय प्रशासन के वायु प्रदूषण को लेकर उदासीन रवैये से नागरिकों के जीवन का संकट बरकरार है। सर्वविदित तथ्य है कि न तो सरकारों के पास पर्याप्त संसाधन हैं और न ही ऐसा विशिष्ट कार्यबल। नागरिकों की जागरूकता व जवाबदेही बढ़ाकर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस विषम एवं ज्वलंत समस्या से मुक्ति के लिये प्रशासन एवं सरकारों को संवेदनशील एवं अन्तर्दृष्टि-सम्पन्न बनना होगा। (लेखक - ललित गर्ग/ ईएमएस)

वृक्षारोपण : अब नहीं तो कब?

उस कोरोना काल को याद कीजिये जब कोविड प्रभावित लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मर रहे थे। पैसे ख़र्च करने पर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। देश के तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स के फ़ेल होने की ख़बरें सुनाई दे रही थीं। शमशान घाट लाशों से पटे पड़े थे। नदियों में लावारिस लाशें तैरती नज़र आ रही थीं। उसी दौरान अनेक समझदार लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पेड़ों पर अपना डेरा बना लिया था। कोई पेड़ के ऊपर चारपाई बांध कर लेटा बैठा रहता था तो तमाम लोग शुद्ध व ताज़ी ऑक्सीजन की चाह में पेड़ों के नीचे पनाह लेने को मजबूर थे। उस दौर में देश के लाखों ग्रामीणों ने तो बग़ीचों में ही अपना लगभग स्थाई अड्डा बना लिया था। गोया महामारी जैसे संकट के उस दौर में भी प्रकृति हमें पेड़ों व दरख़्तों के माध्यम से नि:शुल्क ऑक्सीजन प्रदान कर रही थी। एक युवा पेड़ हमें एक वर्ष में लगभग 7 क्विंटल ऑक्सीजन प्रदान करता है जबकि हमारे लिये हानिकारक व हमारे ही द्वारा विभिन्न माध्यमों से छोड़ी जाने वाली लगभग 20 टन कॉर्बन डाई ऑक्साइड को भी खींच (सोख) लेता है।

आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। गत दस वर्षों से पृथ्वी के लगातार बढ़ते तापमान के कारण पूरे विश्व में ग्लेशियर पिघलने लगे हैं।आदिवासियों से उनके जल जंगल ज़मीनों के अधिकार छीन कर उद्योगपतियों के हवाले किये जा रहे हैं। ब्राज़ील से लेकर भारत तक बड़े पैमाने पर विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई की जा रही है।मिसाल के तौर पर मध्य भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य वन के लाखों पेड़ अडानी द्वारा संचालित परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खदान के विस्तार के लिये स्थानीय ग्रामीणों व आदिवासियों के प्रबल विरोध के बावजूद पुलिस बल की निगरानी में काटे जा रहे हैं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का संकल्प लिया है। प्रचार के अनुसार इसी अभियान के तहत मध्यप्रदेश में साढ़े पांच करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और इसी क्रम में 51 लाख पौधे केवल इंदौर में लगाये जाने की योजना है। इस समय देश का शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जिसने वृक्षारोपण को लेकर सक्रियता न दिखाई हो।

इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इस वर्ष गर्मी का जितना प्रकोप भारत सहित पूरी दुनिया ने झेला उतनी प्रचंड गर्मी पहले कभी नहीं देखनी व सहनी पड़ी। पूरे विश्व में लाखों लोग तेज़ गर्मी की तपिश सहन न करते हुये तड़प कर मर गये। इसलिये इस भीषण गर्मी में भी लोगों को वृक्षों ने आकर्षित किया तथा पेड़ों ने अपनी ज़रूरत का एहसास कराया। ग़ौरतलब है कि एक बड़े वृक्ष के नीचे औसतन चार डिग्री तापमान कम रहता है। साथ ही यही वृक्ष तेज़ धूप की तपिश से भी बचाता है। वर्तमान युग में बढ़ती गर्मी का एक कारक प्रदूषण भी है। प्रदूषण में धुएं के अतिरिक्त धूल मिटटी शोर ग़ुल यानि ध्वनि प्रदूषण का भी अहम योगदान है। परन्तु एक स्वस्थ वृक्ष एक वर्ष में न केवल 20 किलोग्राम से अधिक धूल मिट्टी अपने आप में सोख लेता है बल्कि शोर ग़ुल यानि ध्वनि प्रदूषण को भी कम करता है। इतना ही नहीं बल्कि यही वृक्ष क़रीब 1 लाख वर्ग मीटर प्रदूषित हवा का भी निस्पंदन करता है। यही वृक्ष 80 किलोग्राम पारा, लीथियम व लेड जैसी ज़हरीली धातुओं के मिश्रण को भी सोखने की क्षमता रखता है।

पेड़ पौधों की अहमियत को वैसा तो कोविड काल ने ही लोगों को ठीक से समझा दिया था। ख़ासकर शहरी जीवन बिताने वाले लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही। क्योंकि कोविडकाल के बाद पूरे देश में शहरी इलाक़ों में गमलों व इनमें पौधे लगाने का चलन पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। पक्की फ़र्श वाले मकानों में रखे हुये पर्याप्त मात्रा में गमले में लगे पौधे बेशक एक घर के तापमान को तो नियंत्रित करने व ऑक्सीजन देने की क्षमता तो रखते ही हैं। यह कोविड काल की ही दहशत है जिसके चलते पूरे देश में प्लास्टिक,मिटटी व सीमेंट के गमलों तथा नर्सरीज़ में पौधों की बिक्री कोविड काल के बाद कई गुना अधिक हो चुकी है।

वृक्षों का बादलों से भी गहरा नाता है। आम तौर पर रेगिस्तानी क्षेत्रों में बारिश इसलिए नहीं होती या अत्यधिक कम होती है क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में वृक्ष नहीं होते। जबकि दुनिया में अनेक घने जंगलों के इलाक़े ऐसे भी हैं जहाँ घने जंगलों के कारण अत्यधिक वर्षा होती है। ऐसे घने जंगलों को वर्षावन भी कहा जाता है। गोया वृक्ष,बादल ,बारिश हरियाली मानव जीवन और ख़ुशहाली का आपस में एक दूसरे से सीधा नाता है। नदी नालों के कटाव को रोकने में भी वृक्ष अहम भूमिका अदा करते हैं। यानी बाढ़ रोकने में सहायक होते हैं। हमें अध्ययन करने से तो यहाँ तक पता चलता है कि समुद्री किनारों पर पाए जाने वाले मैंग्रोज़ के पेड़ व इन के घने जंगल सुनामी की गति को नियंत्रित करने तक का काम करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह समुद्री क्षेत्र के विस्तार को भी रोकते हैं। जबकि इन पेड़ों की आधी जड़ें भी धरातल के ऊपर होती हैं।

बहरहाल,वृक्षारोपण को इस समय मानव जीवन के अस्तित्व से जोड़कर देखाने की ज़रुरत है। किसी सरकार,शासन या प्रशासन की तरफ़ मुंह देखने के बजाये जनता को स्वयं इसे जनांदोलन के रूप में लेना होगा और अपनी आदतों में शामिल करना होगा। याद रहे कि सरकारें वृक्षारोपण का शोर कर सकती हैं,इसपर चलाये जाने वाले अभियान का प्रचार कर सकती हैं,इसके नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा सकता है। और तो और लगे लगाये दरख़्तों व जंगलों को कार्पोरेट्स के हित में कटवाने की भागीदार भी हो सकती हैं। विज्ञापनों व साक्षात्कार के माध्यम से इसके महत्व का बखान कर सकती हैं परन्तु चूँकि यह वोट बैंक से जुड़ा विषय नहीं इसलिये इसके प्रति उतनी गंभीरता नहीं दिखातीं जितनी कि ज़रूरत है। लिहाज़ा आज देश के प्रत्येक नागरिक को चाहे वह बच्चा,बूढ़ा,जवान महिला कोई भी हो उसे वृक्षारोपण को अपनी आदतों में शामिल करना होगा। स्वयं उसकी देखभाल व निगरानी करनी होगी।मां के नाम का केवल एक पेड़ ही काफ़ी नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को ख़ासतौर पर वर्षाऋतु में जहाँ और जितने हो सकें अधिकतम वृक्ष लगाने होंगे। इसी अपने जीवन की दैनिक गतिविधियों में शामिल किये जाने की ज़रुरत है। शादी विवाह,मरना जीना ,जन्मदिन मरणदिन विवाह अथवा जन्म या मृत्यु की सालगिरह बरसी प्रत्येक अवसर को यादगार बनाने हेतु हर इन अवसरों पर वृक्षारोपण करें। यदि धरती के बढ़ते तापमान के दौर में वृक्षारोपण के प्रति अब भी हम गंभीर व सक्रीय नहीं हुये तो और कब होंगे ? (लेखक - तनवीर जाफ़री/ईएमएस)

श्रावण मास : शिव भक्ति की कांवड़ यात्रा का पर्व!

भगवान शिव ही एक मात्र ऐसे परमात्मा है जिनकी देवचिन्ह के रूप में शिवलिगं की स्थापना कर पूजा की जाती है। लिगं शब्द का साधारण अर्थ चिन्ह अथवा लक्षण है। चूंकि भगवान शिव ध्यानमूर्ति के रूप में विराजमान ज्यादा होते है इसलिए प्रतीक रूप में अर्थात ध्यानमूर्ति के रूप शिवलिगं की पूजा की जाती है। पुराणों में लयनाल्तिमुच्चते अर्थात लय या प्रलय से लिगं की उत्पत्ति होना बताया गया है। जिनके प्रणेता भगवान शिव है। यही कारण है कि भगवान शिव को प्राय शिवलिगं के रूप अन्य सभी देवी देवताओं को मूर्ति रूप पूजा की जाती है।

शिव स्तुति एक साधारण प्रक्रिया है। ओम नम: शिवाय का साधारण उच्चारण उसे आत्मसात कर लेने का नाम ही शिव अराधना है। श्रावण मास में शिव स्तुति मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है।

हर साल श्रावण मास में करोड़ो की तादाद में कांवडिये सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव कस्बे व शहर वापस लौटते हैं इस यात्राको कांवड़ यात्रा बोला जाता है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी हैं। कांवड के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। पानी आम आदमी के साथ साथ पेड पौधों, पशु - पक्षियों, धरती में निवास करने वाले हजारो लाखों तरह के कीडे-मकोडों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक है। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहां के मैदानी इलाकों में मानव जीवन नदियों पर ही आश्रित है।कांवड़ मेले में हरिद्वार में चारों ओर शिवभक्त नजर आएंगे । गंगोत्री, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार में हर की पेडी से शुरू होकर गंगनहर के समानांतर कांवड़ियों की आस्था की धारा शुरू हो गई है । कांवड़ मेले में जगह-जगह आलोकिक दृश्य देखने को मिलता है।भारतीय लोगों के लिए कांवड़ मेला बिल्कुल अनसुना नहीं है। सावन प्रारंभ होते ही केसरी रंग के कपड़ों में कांवड़िए अपने कंधे पर कांवड़ लटकाकर उसमें गंगाजल भरकर लाते हैं और अपनी मन्नत के अनुसार किसी विशेष शिव मंदिर में उस गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं।गंगाजल लाने और उससे शिवलिंग का अभिषेक करवाने तक का यह पूरा सफर पैदल और नंगे पांव किया जाता है। निश्चित तौर पर यह काम बहुत हिम्मत का है, लेकिन शिव भक्ति के सामने कोई भी मुश्किल नही रहती है।कांवड़ियों के पैरों में पड़ने वाले छाले ही कांवड़ यात्रा में एक बड़ी रुकावट बन जाते हैं लेकिन शिव भक्त हार नही मानते हैं। माना जाता है शिव का जलाभिषेक करने से शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं।सावन के महीने को शिव मास भी कहा जाता है, क्योंकि ये वह महीना होता है जब सारे देवता शयन करते हैं और शिव जाग्रत रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।कांवड़ यात्रा हठयोग की प्रतीक है, लेकिन इस दौरान कावड़ियों को कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है जो अत्यंत आवश्यक होता है।कांवड़ यात्रा शुरू करते ही कावड़ियों के लिए किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित होता है।कांवड़ यात्रा पूरी होने तक उस व्यक्ति को मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करना होता है।

बिना स्नान किए कांवड़ को हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए स्नान करने के बाद ही कांवड़िए अपनी कांवड को छू सकते है।चमड़े की किसी वस्तु का स्पर्श, वाहन का प्रयोग, चारपाई का उपयोग, ये सब कावड़ियों के लिए वर्जित कार्य है। इसके अलावा किसी वृक्ष या पौधे के नीचे भी कावड़ को रखना वर्जित है।कांवड़ ले जाने के पूरे रास्ते भर बोल बम और जय शिव-शंकर का उच्चारण करना फलदायी होता है। कांवड़ को अपने सिर के ऊपर से लेकर जाना भी वर्जित माना गया है।

इन सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है और इसके लिए कांवड़ियों की संकल्पशक्ति की मजबूती अनिवार्य है।श्रावण मास में कावंड में गंगाजल भरकर पदयात्रा करते हुए शिवालयो में जलाभिषेक करना पूण्यप्राप्ति होना माना जाता है। जिस कावंड में गंगाजल भरकर शिवालय में ले जाया जाता है। उस कावंड को बनाने वाले हिन्दू ही नही बल्कि मुस्लमान भी है।हरिद्वार नगरी के ज्वालापुर,सराय में रफीक के परिवार को साल भर की रोजी रोटी इसी कावंड से मिलती है।यह परिवार रंग बिरंगी कांवड़ तैयार कर अपने घर का चूल्हा जलाता है। कई मुस्लमान हिन्दूओं के इस कावंड मेले में कावंड सहायता शिविर लगाकर धार्मिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारे का सन्देश भी देते है।वही इस कावंड मेले को बदरंग करते हुए कुछ कांवडिये भांग का सेवन करते है तो कुछ चरस गांजे का अवैध व्यापार भी इस कावंड मेले की आड में करते है। शिव भक्ति आषाड मास के बीस दिन बीतने के बाद से ही श्रावण मास पूरा होने तक 40 दिन के लिए किये जाने की परम्परा है। जिसकी शुरूआत हो चुकी हैऔर हरिद्वार की सड़कों व हर की पैड़ी पर शिव भक्तो की भीड बढने लगी है। इस बार चार करोड से अधिक कांवडियों के हरिद्वार आकर गंगाजल अपनी कावंड में भरकर ले जाने की सम्भावना है। जिनके लिए हर बार की तरह इस बार भी गंगनहर पटरी मार्ग को कावंड मार्ग बनाया गया है।हालांकि कुछ कांवड़िये राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर भी जाने लगे है।

कावंडियो के लाठी डन्डे लेकर व डीजे बजाकर चलने पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यह प्रतिबन्ध हवा हवाई साबित होगा। क्योकि प्रतिबन्ध के बाद भी कावंडिये लाठी डन्डे लेकर व डीजे बजाकर चलने से नही रूक पाते है। कावंड मेले को सुगम व सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस को जहां कांवडियों के भेष में तैनात किया गया है वही स्वास्थ्य सेवाओ के लिए डाक्टरो की तैनाती,सफाई के लिए पुख्ता इन्तजाम व खादय पदार्थो की शुद्धता व सही रेट वसूलने की हिदायत दी जाती है। इस बार दुकानदारो को अपना नाम दुकान पर अंकित करने की बाध्यता भी की गई है।जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है।परन्तु वास्तव में जब कांवडियो की भीड उमडती है तो पुलिस प्रशासन कांवडियो के सामने बोने होते नजर आने लगते है।

कांवडियो के कारण गंगनहर मार्ग तो आम जनता के लिए बन्द होगा ही और लोग पिरान कलियर तक भी नही जा सकेगे वही राष्टीय राजमार्ग के भी कम से कम एक सप्ताह तक बन्द रहने की बाध्यता है।

जिस कारण स्कूलो,न्यायालयों व सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों का कामकाज प्रभावित होना अवश्यसम्भावी है। सच यह भी है कि कावंड मेले के दिनों में हरिद्वार,रूडकी से लेकर मुज्जफरनगर,मेरठ तक के लोग बन्धक रहेगें। इस कांवड मेले में उत्तराखण्ड के साथ साथ उ0प्र0, राजस्थान, हरियाणा,हिमाचल व पंजाब तक के शिवभक्त कांवडियों के रूप में भाग लेते है।

लेकिन साथ ही असमाजिक तत्वों का भी इस मेले में जमावडा रहता है जिनसे निपटना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। शान्ति,सदभाव और पूण्य प्राप्ति की चाह में शिवभक्त कांवडिये श्रावण मास में कांवड लेने के लिए हरिद्वार आते है और अपनी कांवड में गंगा जल भर पदयात्रा करते हुए उसे अपने अराध्य शिव लिंग पर अर्पित कर पुण्य प्राप्ति करते है। (लेखक- डॉ श्रीगोपाल नारसन /ईएमएस)

शब्द पहेली - 8077

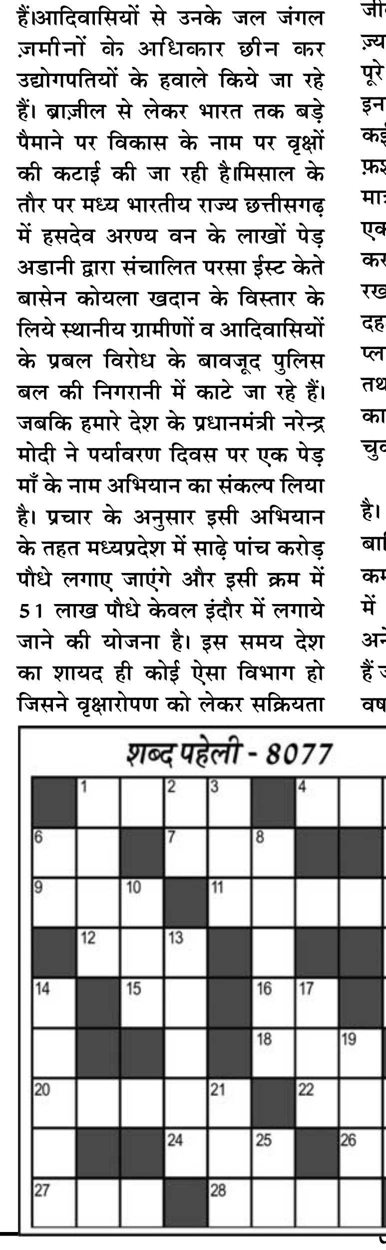

बाएँ से दाएँ

1. अचंभा,आश्चर्य-4
3. अच्छी रुचि,कलात्मक रुचि-3
6. पिता के छोटे भाई,काका-2
7. माह,मास-3
9. धावक(अंग्रेजी-3)
11. नया जीवन,उद्धार होना-5
12. लक्ष्मी,धन की देवी-3
15. बुरी आदत-2
16. पैर,पाँव-2
18. देवमुनि,देवर्षि-3
20. शिकायत करना-5
22. रनिवास-3
24. बेकार,आंवारा-3
26. छोटा टुकड़ा-2
27. अभिनय,कथा मंचन-3
28. सुगंध फैलाना-4

ऊपर से नीचे

1. सहसा,अकस्मात-4
2. एक प्रकार की शराब-2
3. प्रतिभाशाली-3
5. मननशील-5
6. चतुर्थ-2
8. नाव खेना-2,3
10. पासे फैंक कर भविष्य जानने की विद्या-3
13. पैर मारना-5
14. मन की इच्छा-5
17. प्रकार-3
19. टूटना,बिखरना-4
21. पराजित होना, हारना-3
23. चालीस किलो के वजन को यह भी कहते हैं-2
25. पथ,रास्ता,मार्ग-2

शब्द पहेली -8076 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

पेरिस ओलंपिक मेरा अंतिम टूर्नामेंट होगा : मर्रे

पेरिस (ईएमएस)। ब्रिटेन के टेनिस स्टार एंडी मर्रे ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मर्रे ने कहा है कि वह पेरिस ओलंपिक के बाद नहीं खेलेंगे। दो बार के ओलंपिक पुरूष एकल चैम्पियन रहे 37 साल के मर्रे ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अपने अंतिम टेनिस टूर्नामेंट के लिये मैं पेरिस पहुंच गया हूं।

मर्रे ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक 2012 ग्रासकोर्ट पर जीता था जिसमें उन्होंने रोजर फेडरर को तीन सेटों में हराया था। इसके बाद 2016 में हार्डकोर्ट पर जुआन मार्टिन देल पोत्रो को हराकर खिताब जीता था। मर्रे ने 2019 में कूल्हे की प्रत्यारोपण सर्जरी कराई थी। इसके बाद से ही वह फिटनेस से जूझते रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में टेनिस मुकाबले शनिवार से शुरू होंगे। मर्रे का लक्ष्य इसमें जीत से अलविदा कहना होगा।

टेनिस खिलाड़ी वोंड्रोसोवा और हुरकाज पेरिस ओलंपिक से हटे

पेरिस (ईएमएस)। चेक गणराज्य की महिला टेनिस खिलाड़ी मरकेटा वोंड्रोसोवा और पोलैंड के हुबर्ट हुरकाज ने फिट नहीं होने के कारण 26 जुलाई से शुरु हो रहे पेरिस ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया है। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता वोंड्रोसोवा ने चोटिल होने के कारण पेरिस ओलंपिक से हटने की घोषणा की। वहीं पोलैंड के पुरुष टेनिस खिलाड़ी हुबर्ट हुरकाज ने भी घुटने की चोट से कारण ओलंपिक से हटने का फैसला किया। वोंड्रोसोवा ने सोशल मीडिया पर ओलंपिक से हटने की जानकारी देते हुए कहा कि उनका ध्यान अगस्त में होने वाले अमेरिकी ओपन पर है। हुरकाज के भी अमेरिकी ओपन से वापसी पर रहेगा।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए असलंका बने श्रीलंकाई टीम के कप्तान

कोलंबो (ईएमएस)। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) ने भारत के खिलाफ 27 जुलाई से शुरु होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए बल्लेबाज चरिथ असलंका को कप्तान बनाया है। इसका कारण है कि वानिंदु हसरंगा ने टी20 विश्वकप के बाद कप्तानी छोड़ दी थी। असालांका को केवल दो मेचों का अनुभव है। उन्होंने इस साल की शुरूआत में बांग्लादेश दौरे पर दो टी20 मैचों में कप्तानी की थी। वह अंडर 19 टीम के कप्तान रहे हैं। श्रीलंकाई लीग में वह जाफना किंग्स के कप्तान थे और उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलायी थी।

श्रीलंकाई टीम इस प्रकार है :

चरित असालांका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल जनित परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, महीष तीक्षणा, चामिंदु विक्रमसिंघे, मथीसा पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंता चामीरा, बिनुरा फर्नांडो।

पेरिस ओलंपिक के लिए कड़ी की जा रही सुरक्षा , जमीन से लेकर आसमान तक पहरा

पेरिस (ईएमएस)। 26 जुलाई से यहां शुरु होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जा रहे हैं। इसके तहत जहां आसमान में जेट विमान नजर आ रहे हैं। वहीं सड़क पर पुलिसकर्मी और सैनिक गश्त लगाते दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से यहां जिस प्रकार हिंसा की घटनाएं हुई हैं। उसको देखते हुए आयोजमक सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं ले रहे। सरकार ने अन्य देशों से भी इसमें सहायता मांगी है। इसके अलावा ड्रोन और एआई तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है।

सेना की टुकड़ी को किसी भी खतरे से निपटने को कहा गया है जिससे वे खेल स्थल या खेल गांव में आधे घंटे में पहुंच जाये। उद्घाटन समारोह की जगह सीन नदी के किनारों पर भी सुरक्षा अवरोध लगाए जा रहे हैं। यहां 26 जुलाई से 11 अगस्त तक दुनिया भर के लगभग 10,500 खिलाड़ियों के साथ लाखों की संख्या में आने वाले प्रशंसकों की सुरक्षा आयोजन समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इन खेलों पर साइबर हमलों का भी खतरा है। पेरिस खेलों के लिए 45,000 पुलिसकर्मियों के साथ ही लगभग 10,000 सेना के जवानों को तैनात किया गया है।

सुरक्षा इसलिए भी कड़ी की गयी है क्योंकि पेरिस में हाल के कुछ वर्षों में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के बंदूकधारियों और आत्मघाती हमलावरों के हमले बढ़े हैं। इस तरह के हालातों से निपटने के लिए फ्रांस में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर वाहनों पर और पैदल सशस्त्र सैन्य गश्त बढ़ा दी गयी है।

सुरक्षा को बेहतर करने के लिए राफेल युद्धक विमान के साथ हवाई क्षेत्र की निगरानी करने वाली एडब्ल्यूएसीएस निगरानी उड़ानें, रीपर निगरानी ड्रोन, शार्पशूटर से लैस हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निष्क्रिय करने वाले उपकरण पेरिस के आसमान की निगरानी करेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान सीन नदी के आसपास 150 किलोमीटर (93 मील) क्षेत्र को नो फ्लाई जोन करार दिया जायेगा। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से लैस कैमरे भी किसी भी संभावित खतरे से निपटने में मदद करेंगे। सुरक्षा इंतजामों में फ्रांस को 40 से अधिक देशों से भी सहायता मिली है।

श्रीलंका पहुंचने पर भारतीय क्रिकेट टीम का फूलों से हुआ भव्य स्वागत बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है। इस दौरे में भारतीय टीम एकदिवसीय और टी20 सीरीज खेलेगी। टी20 सीरीज के लिए पहली बार कप्तान बनाये गये सूर्यकुमार यादव और नये मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ भारतीय टीम जैसे ही होटल में पहुंची उसका फूल बरसाकर स्वागत हुआ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इस दौरे में भारतीय टीम के सभी मुकाबले पल्लेकल में खेले जाएंगे जबकि कोलंबो में एकदिवसीय सीरीज होगी। टीम इंडिया नए कोच गंभीर के साथ पहली बार किसी विदेशी दौरे पर गयी है। बीसीआई ने टीम के रवाना होने से लेकर श्रीलंका पहुंचने तक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया है।

एयरपोर्ट पर कप्तान सूर्यकुमार के साथ स्टाफ की सदस्य फोटो खिंचवाती दिखीं। फ्लाइट और फिर टीम बस में सभी खिलाड़ी मस्ती करते दिखे। वहीं कोलंबो में पहुंचने के बाद जब टीम इंडिया के खिलाड़ी होटल पहुंचे तो फूलों से उनका स्वागत हुआ। भारतीय टीम को यहां 27 जुलाई से तीन मैचों की टी20 जबकि 2 अगस्त से इतने ही मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेलनी है। एकदिवसीय सीरीज की कप्तानी नियमित कप्तान रोहित शर्मा करेंगे।

गंभीर के मुख्य कोच बनने के साथ ही कोचिंग स्टाफ भी बदला

अभिषेक और डोशटे श्रीलंका दौरे में सहायक कोच के तौर पर शामिल

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के नये मुख्य कोच के रूप में गौतम गंभीर के कार्यभार संभालने के बाद भारतीय टीम को कोचिंग स्टाफ भी बदल गया है। श्रीलंका दौरे के लिए सहायक कोच के रूप में अभिषेक नायर और रेयान टेन डोशटे को शामिल किया गया है। अब गंभीर , अभिषेक और डोशटे की पहली परीक्षा 27 जुलाई से शुरू हो रही टी20 सीरीज में होगी। कोचिंग स्टाफ में राहुल द्रविड़ के कार्यकाल के दौरान के कुछ सदस्य भी शामिल हैं। इसमें टी दिलीप को फील्डिंग कोच के रूप में रखा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) से जुड़े साईराज बहुतुले को इस दौरे के लिए अंतरिम गेंदबाजीत कोच के तौर पर रखा गया है क्योंकि पूर्णकालिक गेंदाबाजी कोच के लिए अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है।

गंभीर ने कहा कि वह बीसीसीआई की कार्यप्रणाली से खुश हैं। बोर्ड ने उन्हें लगभग सभी वो चीजें दी, जिसकी उन्होंने मांग की थी। गौतम ने कहा, मैंने जो चीजें मांगी हैं, उनमें से ज्यादातर पर वे सहमत हो गए हैं। अभिषेक और रयान सहायक कोच के रूप में काम करेंगे ये दोनो ही काफी पेशेवर है जो मैंने आईपीएल में इनके साथ काम करते हुए अनुभव किया है ।

टेनिस खिलाड़ी वोंड्रोसोवा और हुरकाज पेरिस ओलंपिक से हटे

पेरिस (ईएमएस)। चेक गणराज्य की महिला टेनिस खिलाड़ी मरकेटा वोंड्रोसोवा और पोलैंड के हुबर्ट हुरकाज ने फिट नहीं होने के कारण 26 जुलाई से शुरु हो रहे पेरिस ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया है। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता वोंड्रोसोवा ने चोटिल होने के कारण पेरिस ओलंपिक से हटने की घोषणा की। वहीं पोलैंड के पुरुष टेनिस खिलाड़ी हुबर्ट हुरकाज ने भी घुटने की चोट से कारण ओलंपिक से हटने का फैसला किया। वोंड्रोसोवा ने सोशल मीडिया पर ओलंपिक से हटने की जानकारी देते हुए कहा कि उनका ध्यान अगस्त में होने वाले अमेरिकी ओपन पर है। हुरकाज के भी अमेरिकी ओपन से वापसी पर रहेगा।

बजट के बाद गिरा बाजार , सेंसेक्स 73 और निफ्टी 30 अंक नीचे आया

मुम्बई (ईएमएस)। बजट के बाद घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गयी। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट बजट में वायदा और विकल्प प्रतिभूतियों (एफएंडओ) पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाये जाने से आई। इससे प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 73 अंक नीचे आकर 80,429 के स्तर पर जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 30 अंक फिसलकर 24,479 के स्तर पर बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही 2024-25 का बजट पेश किया। बीएसई सेंसेक्स ऊपर आने लगा पर कुछ ही देर में इसमें गिरावट आने लगी। दोपहर में यह 1,266.17 अंक फिसलकर 79,235.91 अंक पर पहुंच गया। बजट के बाद निफ्टी भी ऊपर आया।

सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 264.33 अंक चढ़कर 80,766.41 अंक पर पहुंच गया था। निफ्टी 73.3 अंक ऊपर आकर 24,582.55 अंक पर रहा था।

सीतारमण ने कहा कि सरकार मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्ग के लिए कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ छूट की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की योजना बना रही है। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने एफएंडओ पर एसटीटी में 0.02 फीसदी और 0.1 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की। सेंसेक्स की कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बजाज फिनसर्व के शेयर में सबसे अधिक गिरावट आई है। वहीं टाइटन, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में उछाल आया।

दूसरी ओर एशियाई बाजार आज मिला-जुला कारोबार हुआ। जापान के निक्केई में 0.20 फीसदी की तेजी जबकि हॉन्गकॉन्ग के हैंगसेंग में 0.12 फीसदी की गिरावट रही। चीन का शंघाई कंपोजिट 0.51फीसदी नीचे आया। विदेशी निवेशकों ने गत दिवस 3,444.06 करोड़ के शेयर खरीदे। वहीं सोमवार को

अमेरिकी बाजार डाओ जोंस , नेसडेक ऊपर आया। इसके अलावा एसएंडपी में भी 1.08 फीसदी की तेजी रही। इससे पहले आज सुबह बजट पेश करने के दिन घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। बाजार के प्रमुख इंडेक्स लाभ के साथ ही हरे निशान में कारोबार करते दिखे। बीएसई सेंसेक्स 239 अंक ऊपर 80,741 पर कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी50 66 अंक ऊपर 24,575 के आसपास कारोबार करता दिखा। वहीं व्यापक बाजारों में बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स 0.3 फीसदी की बढ़त के साथ शुरू होने के बाद लाल निशान में आ गए।

अंतरिम से आम बजट तक.....इन सेक्टर ने दिया बंपर रिटर्न

नई दिल्ली (ईएमएस)। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बुधवार को पहला बजट पेश किया है। चुनाव से पहले अंतरिम से आम बजट के दौरान कई सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। मोदी सरकार की तरफ से भी कैपेक्स में इजाफा करने की वजह से भी तेजी देखने को मिली है। पिछले कई बजट में लगातार देखने को मिला है कि रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर पर सरकार का बड़ा फोकस है।

फरवरी 2024 से अबतक बीएसई पीएसयू इंडेक्स के 22 कंपनियों के शेयरों का भाव 30 प्रतिशत से 195 प्रतिशत बढ़ा है। सबसे अधिक तेजी कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिली है। इस स्टॉक का भाव फरवरी 2024 से अबतक 912 रुपये से 2600 रुपये को पार कर गया है। यानी करीब 195 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

अन्य डिफेंस कंपनियों में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएमएल और बीएचईएल के शेयरों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। ये स्टॉक 40 प्रतिशत से 125 प्रतिशत तक का रिटर्न देने में सफल हुए हैं। बता दें, भारत का डिफेंस सेक्टर तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। मौजूदा समय में भारत 85 देशों को एक्सपोर्ट करता है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी भारत आज 60 प्रतिशत हथियारों को विदेशों से खरीदता है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि 2030 तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स को 50000 करोड़ रुपये तक पहुंचाया जाए।

सऊदी सरकार का फैसला, अब स्थानीय लोगों को दी जाएगी नौकरी, भारतीयों पर मंडराने लगा खतरा

रियाद,(ईएमएस)। सऊदी अरब की सरकार ने नौकरियों में स्थानीय लोगों को ज्यादा मौका देने का फैसला लिया है। सऊदी अरब ने निजी क्षेत्र में 25 फीसदी इंजीनियरिंग नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी हैं। नौकरियों को लोकेलाइज करने का यह फैसला 21 जुलाई से लागू कर दिया गया है।

देश के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय, नगर निगम और आवास मंत्रालय ने इस संबंध में ये फैसला किया है। स्थानीयकरण का ये फैसला इंजीनियरिंग व्यवसायों में पांच या उससे ज्यादा कामगारों को रोजगार देने वाले निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। छोटे प्रतिष्ठानों, जिनमें कर्मचारियों की संख्या चार तक है, वहां ये नियम लागू नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ये फैसला कई क्षेत्रों में देश के पुरुष और महिला नागरिकों के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करेगा। सऊदी के इस फैसले से स्थानीय लोगों को नौकरी मिलने में आसानी होगी। देश में केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, फ्लाइट इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जॉब काफी संख्या में हैं।

सऊदी सरकार ने इंजीनियरिंग में रोजगार बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। प्रतिष्ठानों को मदद के लिए मानव संसाधन विकास कोष एचएडीएएफ ने प्रोत्साहन और सहायता, भर्ती प्रक्रियाओं और उपयुक्त श्रमिकों की खोज, प्रशिक्षण और व्यावसायिक योग्यता, भर्ती प्रक्रिया और कैरियर निरंतरता का समर्थन का फैसला लिया है। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने 2030 तक बेरोजगारी को सात फीसदी तक कम करने के लिए कई क्षेत्रों में श्रमिकों के सऊदीकरण की घोषणा की है, जो आय स्त्रोतों में विविधता लाने और तेल पर निर्भरता को कम करने के विजन 2030 के लक्ष्य के अनुरूप है।

सऊदी सरकार के इस फैसले का सीधा असर भारतीय कामगारों पर भी होगा। सऊदी में काम करने वालों की संख्या करीब 26 लाख है। सऊदी में भारतीय करीब हर क्षेत्र में नौकरियां कर रहे हैं। इसमें ड्राइवर, सफाईकर्मी, रसोइया, नर्स के अलावा इंजीनियरिंग क्षेत्र की नौकरियां शामिल हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 के तहत सऊदी अरब के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। इसी क्रम में सऊदी में नौकरियों में आरक्षण का फैसला लिया गया है।

छात्र यहां बसने की उम्मीद लेकर ना आएंः कनाडा

- पढ़ाई खत्म कर जाना होगा वापस

ओटावा (ईएमएस)। कनाडा के इमिग्रेशन मिनस्टर ने भी एक बयान में कहा है कि स्टडी वीजा पर आने वाले छात्र यहां बसने की उम्मीद लेकर ना आएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय और विक्टोरिया विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों का कहना है कि उनके अंतरराष्ट्रीय छात्र नामांकन स्तर पहले से ही 30 प्रतिशत की सीमा से नीचे हैं।

ऐसे में नई गाइडलाइन से उन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांक क्वांटलेन पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय ने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए अपने 36 प्रतिशत नामांकन के साथ नई सीमा को पार कर लिया है। इस महीने प्रभावी होने वाले दिशानिर्देशों में आगामी वर्ष से तय समय सीमा को फॉलो करना होगा। कनाडा सरकार वर्तमान में तेजी से जनसंख्या वृद्धि के बीच आप्रवासन को धीमा करने के प्रयास में विदेशी छात्रों के लिए दीर्घकालिक वीजा जारी करने की भी समीक्षा कर रही है।

इमिग्रेशन मिनस्टर मार्क मिलर ने विदेशी छात्रों की संख्या को घरेलू बाजार की मांग के अनुपात में रखने पर जोर दिया है। कनाडा की नीति शिक्षित आप्रवासियों और छात्रों का स्वागत करने की रही है लेकिन हालिया समय में उसकी नीति में बदलाव आया है। मंत्री मिलर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि स्टडी वीजा को कनाडा में बसने की गारंटी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। स्टडी वीजा पढ़ाई की इजाजत देता है और उसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए। बता दें कि कनाडा में विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया (बीसी) प्रान्त की सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

बीसी सरकार ने सार्वजनिक पोस्ट सेकेंडरी संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय छात्र नामांकन को कुल छात्रों के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन एंड स्किल मिनिस्ट्री ने कहा है कि छात्रों के नामांकन की सीमा तय करने का मकसद संस्थानों पर दबाव कम करना है। गाइडलाइन में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रणनीतिक योजना प्रस्तुत करनी होगी। कॉलेजों की निगरानी प्रांत के प्रशासन की ओर से की जाएगी।

अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल ने 23 जुलाई, मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर हमले के 10 दिन बाद आया है।

चीटल पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाने के आरोप लग रहा था। इसी सिलसिले में चीटल सोमवार को संसद की कमेटी के सामने पेश हुई थीं। चीटल ने कमेटी से कहा था, ट्रम्प की सुरक्षा में चूक हुई है। एजेंसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। हालांकि, उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था।

13 जुलाई को ट्रम्प पर पेंनसिल वेनिया की एक रैली में जानलेवा हमला हुआ था। उनके कान में चोट आई थी। संसद की कमेटी को चीटल कुछ जानकारी देने से इनकार कर दिया था। ट्रम्प के हमलावर ने जिस वेयर हाउस की छत से गोली चलाई थी, उसे सीक्रेट सर्विस ने सिक्योरिटी जोन में शामिल नहीं किया था। ये वेयर हाउस ट्रम्प के मंच से सिर्फ 400 फीट की दूरी पर था। चीटल से जब पूछा गया कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स वहां पर तैनात क्यों नहीं थे, इस पर उन्होंने कुछ नहीं बताया।

हत्या के प्रयास मामले में नहीं हो सकती दस साल से ज्यादा की सजा

नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराए गए शख्स को दस साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आजीवन कारावास की सजा ना मिली हो तो अपराधी को इससे ज्यादा अवधि तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। आईपीसी की धारा 307 के तहत सज़ा को स्पष्ट करते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और राजेश बिंदल की युगलपीठ ने हत्या के प्रयास के मामलों के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा का पालन करने का आदेश दिया है।

रेशम के धागे से बनेंगी दवाइयां और सेरी बैंडेज

भोपाल (ईएमएस)। रेशम के धागे से दवाइयां और सेरी बैंडेज बनाने के लिये मंगलवार को नर्मदापुरम सिल्क इन्क्यूबेटर एवं शासकीय सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल के बीच मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टेन्डिंग (एमओयू) हुआ। ऐसा नवाचार करने के मामले में मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल की विशेष रूचि एवं पहल पर टेक टॉक के तहत फाइब्रोहिल कंपनी के विवेक मिश्रा एवं शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल के.वी. राव के बीच में हुए इस एमओयू के तहत अब रेशम से सेरी बैंडेज बनाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सतपुड़ा एवं नर्मदा के वनों का ककून अत्यंत शुद्ध एवं प्रदूषण रहित माना जाता है। उन्हीं ककून से दवाइयां बनायी जायेंगी। इससे पावडर, क्रीम, सेरी बैंडेज, सिजेरीयन ड्रेसिंग, डायबिटिक घाव की ड्रेसिंग तथा ऑपरेशन के बाद की ड्रेसिंग भी बनायी जा सकेंगी। रेशम घाव को गीला नहीं रखता एवं शरीर के साथ भी नहीं चिपकता तथा रेशम से फायब्रोयिन नामक प्रोटीन निकलता है, जो जख्मों, डायबिटिज से ऊगंलियों में होने वाले घाव एवं गर्भवती महिलाओं के सर्जिकल डिलीवरी के घाव कम समय में ठीक करता है तथा इससे संक्रमण की संभावना भी नगण्य हो जाती है। वर्तमान में प्राणियों के कॉलिजन से बैंडेज बनता था, जिसका रेशम एक अत्यंत बेहतर व टिकाऊ विकल्प है। रेशम से समृद्धि योजना के तहत कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा वर्तमान में रेशम उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन सहायता दी जाती है। इसके अलावा रेशम से दवाइयां व बैंडेज बनने से किसानों के रेशम की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से उनकी आय में डेढ़ से दो गुना वृद्धि हो सकेगी।

रेशम से दवाइयां व बैंडेज बनाने की नवाचार प्रक्रिया से म.प्र. के किसानों का ककून अधिक क्रय होगा। साथ ही उन्नत किस्म के रेशम के धागे के अलावा दवा फैक्ट्री खोलकर ऐसी दवा का निर्यात भी होगा। रेशम के धागे से निर्मित होने वाली दवा बाजार दर से 30 प्रतिशत सस्ती होगी। इन दवाइयों को ड्रग्स कंट्रोलर, भारत सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई है। फिलहाल यह एक शुरुआत है, आगे चलकर नर्मदापुरम जिले में एक फार्मा फैक्ट्री भी स्थापित की जा सकती है। म.प्र. भंडार क्रय नियम के तहत गॉज बैंडेज बिना निविदा के सीधे क्रय किये जा सकते थे, जो अब सीधे कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग से ही क्रय किये जा सकेंगे। रेशम से समृद्धि लाने की दिशा में आज हुआ एमओयू ।

देश में ड्रोन उड़ाने के लिए 16,000 आरपीसी जारी किए गएः सरकार

नई दिल्ली (ईएमएस)। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा को बताया कि देश में ड्रोन उड़ाने के लिए 16,000 से ज्यादा रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (आरपीसी) जारी किए गए हैं। ये सर्टिफिकेट डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट ट्रेनिंग संगठनों (आरपीटीओ) द्वारा जारी किए गए हैं। मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में यह भी बताया कि देश में 48 ड्रोन कंपनियां डीजीसीए द्वारा प्रमाणित ड्रोन मॉडल बना रही हैं और रेगुलेटर द्वारा 70 मॉडल को प्रमाणित किया गया है। उन्होंने कहा ?कि भारत में ड्रोन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। अब तक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अप्रूव्ड आरपीटीओ द्वारा 16,000 रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (आरपीसी) जारी किए गए हैं। डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड 116 आरपीटीओ हैं।

भारत का शोध एवं विकास पर खर्च अन्य देशों की तुलना में कमः सर्वे

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत शोध एवं विकास (आरएंडडी) में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले देश का खर्च चीन, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है। यह बात एक इकनॉमिक सर्वे 2023-24 में कही गई है। इकनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि आरएंडडी में निजी क्षेत्र का योगदान भी कम है। संसद में पेश किए गए दस्तावेज के अनुसार, जीईआरडी (आरएंडडी पर सकल व्यय) को अनुसंधान नतीजों में बेहतर ढंग से बदलने के लिए उच्च शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान के बीच संबंध को मजबूत करना चाहिए। इकनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया कि भारत में संस्थान तकनीक विकसित करते हैं, लेकिन लोगों के लाभ के लिए प्रयोगशाला से समाज तक पहुंचने की उनकी दर कम है। इसमें कहा गया है ?कि भारत आरएंडडी में तेजी से प्रगति कर रहा है, वित्त वर्ष 2019-20 में 25,000 से कम पेटेंट मंजूरी की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग एक लाख पेटेंट दिए गए हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के आंकड़ों का हवाला देते हुए इकनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि भारत ने 2022 में पेटेंट दाखिल करने में सबसे अधिक वृद्धि (31.6 प्रतिशत) दर्ज की। जीआईआई (2023) के अनुसार भारत ने 2015 में 81वें स्थान से 2023 में 40वें स्थान पर पहुंचने में सफल रहा है।

चीन के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर घटाई

बैंकॉक (ईएमएस)। चीन के केंद्रीय बैंक ने अपनी पांच वर्षीय प्रमुख ऋण दर और एक वर्षीय दर दोनों में कटौती कर दी है। यह फैसला उसके संपत्ति क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ?किया गया है। पांच साल की दर में 10 आधार अंकों की कटौती की गई जिससे यह 3.95 प्रतिशत से 3.85 प्रतिशत हो गई है। एक साल की दर को 3.45 प्रतिशत से घटाकर 3.35 प्रतिशत कर दिया गया। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने बैंकों के लिए अपनी मध्यम अवधि की ऋण सुविधा के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को भी कम कर दिया है। बैंक ने कहा कि इसका मकसद बॉन्ड बाजार पर दबाव कम करना है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद से गति हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। इसमें संपत्ति बाजार में मंदी एक बड़ी बाधा रही है। आर्थिक वृद्धि दर पिछली तिमाही में गिरकर 4.7 प्रतिशत हो गई, लेकिन वर्ष की पहली छमाही के लिए यह सरकार के लक्ष्य (पांच प्रतिशत) के आसपास बनी रही।

15 राज्यों के गवर्नर हेरिस के समर्थन में, लोकप्रियता में ट्रंप पिछड़े

न्यूयॉर्क (ईएमएस)। वर्तमान राष्ट्रपति वाइडेन के चुनाव मैदान से हटने और कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आने के बाद, अमेरिका की राजनीति में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कमला हैरिस का नाम सामने आते ही रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में 10 फ़ीसदी की गिरावट देखी जा रही है। जिन राज्यों से ट्रंप को भारी समर्थन मिल रहा था। उन राज्यों में भी कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद ऑनलाइन सर्वे में ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट आई है।

कमला हैरिस को 24 घंटे के अंदर 15 डेमोक्रेटिक गवर्नर तथा 55 सीनेटरों का समर्थन मिला है। राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का नाम सामने आते ही, अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रणनीति को बदलना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस के पक्ष में जो सहानुभूति की लहर चल रही है। उसका मुकाबला करना पड़ेगा।

कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति पद के लिए पहली अश्वेत महिला हैं। अमेरिका की 25 फ़ीसदी आबादी अश्वेत मतदाताओं की है। कमला हैरिस गर्भपात के अधिकार की समर्थक रही हैं। कमला हेरिस अटॉर्नी रह चुकी हैं। वह ट्रंप के क्रिमिनल रिकॉर्ड को चुनावी प्रचार का हथकंडा बनाएंगी। ट्रंप के लिए कमला हेरिस को घेरना अब मुश्किल हो जाएगा।

कमला हैरिस की उम्मीदवारी घोषित होते ही 10 घंटे के अंदर 435 करोड रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ। 2020 के चुनाव में एक दिन के अंदर 295 करोड रुपए का रिकॉर्ड चंदा एकत्रित हुआ था। इस बार 10 घंटे में ही 435 करोड रुपए इकट्ठे हो गए।

अमेरिका के फ्लोरिडा का फोर्ड लाडरडेल अरबपतियों का नया पसंदीदा शहर

न्यूयॉर्क (ईएमएस)। अमेरिका के फ्लोरिडा का फोर्ट लाडरडेल शहर अरबपतियों का नया ठिकाना बन रहा है। फ्लोरिडा के इस शहर में बड़ी संख्या में अरबपति आकर बस रहे हैं। यहां की प्रॉपर्टी में याटपार्क करने की सुविधा है। जैफ बेजोस,कैन ग्रिफिन,लियोनेल मेसी जैसे दिग्गज यहां पर प्रॉपर्टी ले चुके हैं। अन्य अरबपति और ख़रबपति भी यहां प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में यहां संपत्तियों की कीमतें बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। डेढ़ साल पहले जो बंग्ला ढाई सौ करोड रुपए का था। अब वह 400 करोड रुपए में बिका है। कहा जा रहा है, अरबपतियों का यह नया गढ़ बन गया है। जिसके कारण आने वाले समय में यहां प्रॉपर्टी की कीमत और भी तेजी के साथ बढ़ेगी।

निर्यात में राहत दे सकती है सरकार, चावल के बढ़ेंगे भाव

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ?चावल निर्यात में राहत देने की तैयारी कर रही है। दरअसल, वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति चावल की कुछ किस्मों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा की जरूरत पर विचार कर रही है। अगर प्र?तिबंध हटाया गया तो फिर चावल की कीमत बढ़ना तय है। वहीं आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल जुलाई-अगस्त में चावल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों से बासमती की तुलना में गैर-बासमती चावल पर ज्यादा असर पड़ा है।

सूत्रों ने कहा कि समिति जल्द ही चावल की कुछ किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील देने को लेकर दिए गए सुझावों पर विचार करेगी, क्योंकि इसका केंद्रीय पूल में भंडार जरूरत से ज्यादा हो गया है। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि समिति प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला खरीफ में धान की बोआई की स्थिति साफ होने तक के लिए टाल सकती है।

अगले महीने से केंद्र सरकार खुले बाजार में चावल बेचना शुरू करने जा रही है। केंद्र ने राज्यों को बगैर किसी निविदा के उससे चावल खरीदने की अनुमति भी दे दी है इस चावल की बिक्री 28 रुपये किलो होगी। इस फैसले से कई राज्य, खासकर दक्षिण भारत के राज्य अपनी खाद्यान्न योजना फिर से शुरू कर सकेंगे। इस बात की भी संभावना है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का अतिरिक्त चावल एथनॉल बनाने के लिए भी दिया जाए, जो पिछले कुछ महीने से रुका हुआ है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि अनाज से एथनॉल बनाने वाले सरकार पर (ओएमसी) द्वारा एथनॉल की एफसीआई के गोदामों से सस्ते खरीद दर में वृद्धि करने की मांग की चावल की आपूर्ति बहाल करने की थी, मांग कर रहे हैं।

उनका तर्क है कि ऐसा न होने से उनके संयंत्र बंद हो जाने खतरा है। उनका कहना है कि पिछले 6 महीने में खुले बाजार में टूटे चावल की कीमत औसतन 22 से 24 रुपये किलो से बढ़कर 27 से 29 रुपये किलो हो गई है। मक्के की कीमत भी औसत 22 से 23 रुपये किलो से बढ़कर 26 से 27 रुपये किलो पहुंच गई है। इस कीमत पर भी आपूर्ति सीमित है।

राष्ट्रीय सहयोग नीति पर काम जारीः वित्त मंत्री

नई दिल्ली (ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाने पर ?विचार कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा, जबकि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण तथा विपणन को मजबूत करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि और रोजगार के अवसरों का सृजन नीतिगत लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार झींगा पालन और विपणन के लिए भी वित्त उपलब्ध कराएगी।

भूकंप के झटकों से हिला टोक्यो, लोग घरों से आए बहार, कोई नुकसान नहीं

टोक्यो,(ईएमएस)। जापान की राजधानी टोक्यो के उत्तर-पूर्व में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस लगे। जापानी मौसम विभाग ने बताया कि सुबह 10:07 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। भूकंप से जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है लेकिन, झटकों के बाद लोग डर गए और घरों से बाहर निकल कर सड़क पर आ गए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप की गहराई का केंद्र 90 किलोमीटर था। जो उत्तरी इबाराकी प्रांत के 36.8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 140.8 डिग्री पूर्वी देशांतर के करीब आया। भूकंप के झटके मध्य टोक्यो तक महसूस किए गए। जापानी मौसम विभाग ने सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। बता दें कि जून 2024 में भी जापान में भूकंप के झटके लगे थे। जापान के फुकुशिमा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई।

देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम पर आधारित होती हैं। भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के आधार पर कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं। जिसके बाद हर रोज सरकारी तेल कंपनियों पेट्रोल और डीजल का नए भाव अपडेट करती है। तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल-डीजल की नई दरें जारी कर दी है। आज आम बंजट पेश होने जा रहा है, ऐसे में आज देश के कई राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल के दाम घट गए हैं जबकि कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ गयी है। बिहार में पेट्रोल 44 पैसे घटकर 106.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल 41 पैसे घटकर 93.61 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। यूपी में पेट्रोल 12 पैसे घटकर 94.25 रुपये प्रति लीटर और डीजल 14 पैसे घटकर 87.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं, महाराष्ट्र में भी पेट्रोल-डीजल सस्ता हो गया है। यहां पेट्रोल के दाम 20 पैसे घटकर 104.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 20 पैसे घटकर 90.77 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल की कीमत 91.76 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है।

नुकसान दायक साबित हो सकती है वियाग्रा

लंदन (ईएमएस)। वियाग्रा दवा सीलदेनाफिल के ब्रैंड का नाम है, इस लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। 18 साल और इससे ऊपर उम्र के लोग ही यह दवा खरीद सकते हैं। आसान भाषा में समझ सकते हैं कि दवा से प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इससे इरेक्शन मेनटेन रहता है और इंटरकोर्स पॉसिबल हो पाता है। हालांकि बिना एक्सपर्ट सलाह के इस दवा को लेना काफी नुकसानदायक होता है। रिपोर्ट के मुताबिक, वियाग्रा लेने के 1 घंटे बाद ही काम करना शुरू कर देती है। यह भी पॉसिबल है कि यह खाने के आधे घंटे बाद काम करना शुरू कर दे और यह भी संभव है, कि 4 घंटे तक इसका असर न हो। अगर आपको डॉक्टर ने यह दवा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए लिखी है और इसका असर नहीं दिख रहा, तब खुद से डोज कभी भी न बढ़ाएं। हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार दवा सीलदेनाफिल जो कि वियाग्रा के नाम से मिलती है, लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारी के केस में दी जाती है। इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है। ट्रीटमेंट के दौरान इस 30 से 100 एमजी तक दिया जाता है। जब इस दवा को हाई डोज में ले लिया जाता है, तब ब्लड प्रेशर गिर जाता है। बीपी इतना लो हो जाता है कि हार्ट और ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। इस ब्रेन और हार्ट में स्कीमिया हो जाता है।

हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि इरेक्टाइटल डिसफंक्शन के लिए यह दवा आईवी यानी इंजेक्शन के रूप में कतई नहीं लेनी चाहिए। इससे ओरल दवा लेने की तुलना में ज्यादा नुकसान होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ओरल और आईवी दवाओं से बचना ही बेहतर है।

लोकल ऑइंटमेंट या इरेक्शन पंप आते हैं जिनका इस्तेमाल सेफ रहता है। डॉक्टर ने बताया कि बिना हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के वियाग्रा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वियाग्रा के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए इस पर बैन लग जाना चाहिए।

पाकिस्तान के अज़्म-ए-इस्ते-हकम के विरोध में उतरी आवाम

- राज्य सरकारों ने भी विशेष अभियान को लेकर दी चेतावनी

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ एक विशेष अभियान ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकम के शुरू होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। पहले तो खुद पाकिस्तान की जनता ने इस अभियान का विरोध किया था, अब राज्य सरकारों ने भी सेना के इस कदम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खास बात ये है कि सेना के इस अभियान के खिलाफ बाकायदा राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव भी पास किया गया है। उधर, इस ऑपरेशन को लेकर एक अन्य जिहादी संगठन ने पाकिस्तानी सेना के साथ चीनी ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में आतंकवादियों के सफाए के लिए ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम का ऐलान किया था। इसके बाद से कथित आतंकवादियों और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच लगातार संघर्ष जारी है।

इस अभियान में आतंकवादियों के नाम पर आम जनता को भी निशाना बनाया जा रहा है। सेना के इस जुल्म के खिलाफ वहां विरोध शुरू हो गया है। जनता के उत्पीड़न के खिलाफ राज्य सरकारें भी सेना के विरोध में उठ खड़ी हो गई हैं। इस सैन्य अभियान के विरोध को लेकर खैबर पख्तूनख्वा राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें कहा गया कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि वह स्थायित्व देगा, पूरी तरह से अफवाह है। विधानसभा में बिल पास करते हुए खैबर पख्तूनख्वा सरकार द्वारा कहा गया कि इस तरह के किसी भी ऑपरेशन को चलाए जाने के पहले केंद्र को प्रांतीय सरकार और उसके निर्वाचित सदन को विश्वास में लेना चाहिए था। इस अभियान के परिणाम मिलने की जगह गंभीर नुकसान ही हो रहा है जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है।

अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव-प्रचार अभियान का नाम बदला है, मिशन नहीं

बाइडेन बोले- हैरिस का दिल खोलकर समर्थन करें और एकजुट होकर ट्रंप को हराएं

वाशिंगटन,(ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी को चौंकाते हुए राष्ट्रपति चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। बाइडेन ने अपने फैसले का समर्थन करते हुए इसे सही बताया है। उन्होंने कहा कि वह कमला हैरिस के लिए धुंआधार प्रचार करेंगे। बाइडेन ने अपने समर्थकों से अपील की है कि हैरिस का उसी तरह समर्थन करें, जैसा मेरा करते आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार अभियान का नाम बदला है लेकिन मिशन नहीं बदला है और हमारा मिशन है, डोनाल्ड ट्रंप को हराना।

बाइडेन ने कहा कि अगर मुझे कोरोना नहीं होता तो मैं आपके साथ यहां बैठा होता, आपके साथ खड़ा होता. आप लोगों ने जो किया है, मुझे उस पर गर्व है। कोरोना की वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा हूं लेकिन जल्द ही लोगों के बीच आऊंगा. मैं कहीं नहीं जा रहा. मैं चाहता हूं कि लोग ये याद रखें कि हमने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने चुनाव प्रचार टीम से आग्रह किया है कि वे हैरिस का दिल खोलकर समर्थन करें और एकजुट होकर ट्रंप को हराएं।

बाइडेन ने कहा कि बेशक चुनाव प्रचार अभियान का नाम बदला गया है लेकिन हमारा मिशन नहीं बदला है। मैं हैरिस का प्रचार करूंगा। हमें लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। ट्रंप हमारे समुदाय और देश के लिए खतरा है। मेरे विदेश नीति सहयोगियों, मेरे समकक्षों और दुनियाभर के लोगों से पूछिए वह अभी भी खतरा बने हुए हैं। मुझे यकीन है कि आपने जिस तरह की मेहनत मेरे लिए की है, आप वैसी ही मेहनत हैरिस को जिताने में भी करेंगे।

बता दें कि बाडेन ने रविवार को चिट्ठी लिखकर अचानक से राष्ट्रपति चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन का यह फैसला तब आया, जब डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता और उनके समर्थक उनसे नाम वापस लेने की अपील कर रहे थे।

सोना के भाव बढ़कर 72,800, चांदी गिरावट के साथ 89,000 रुपए

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार के आम बजट पेश होने से पहले मंगलवार को सोने के वायदा कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई, जबकि चांदी के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 72,800 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 89,000 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सोने के वायदा भाव तेजी के साथ खुले, जबकि चांदी के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। सोने के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रेक्ट 120 रुपये की तेजी के साथ 72,838 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह कॉन्ट्रेक्ट 100 रुपये की तेजी के साथ 72,818 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रेक्ट 205 रुपये की गिरावट के साथ 88,995 रुपये पर खुला। इस समय यह 213 रुपये की गिरावट के साथ 88,990 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। चांदी के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। कॉमेक्स पर सोना 2,398 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव प्राइस 2,394.70 डॉलर प्रति औंस था। ?फिलहाल यह 3.90 डॉलर की तेजी के साथ 2,39 8.60 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 29.31 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव भी 29.32 था। ?फिलहाल यह 0.14 डॉलर की गिरावट के साथ 29.17 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

सड़कें बनीं नदियां, डुंभाल में १५० घरों में भरा खाड़ी का पानी

निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, ५०० परिवार प्रभावित, सूरत जिले के पलसाणा तालुका का बलेश्वर गांव डूबा

सूरत, २३ जुलाई। सूरत शहर में रविवार शाम ६ बजे से शुरू हुई बारिश सोमवार को भी जारी रही। २४ घंटे में साढ़े ९ इंच बारिश होने से जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। शहर की कई सड़कों पर घुटने तक पानी भरने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह तो सड़कों पर भरे पानी में वाहन बंद पड़ गए थे। शहर के मीठी खाड़ी क्षेत्र में १५० घरों में पानी भर गया।

पूरा इलाका तालाब बन जाने से ४०० घरों के लोग प्रभावित हैं। दुकानों में भी पानी भर गया है। इससे दुकानें खुली ही नहीं। लोगों को खाने-पीने के सामान नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि रविवार शाम २ घंटे में ही चार इंच पानी बरसा था। उसके बाद रातभर बारिश हुई। सोमवार सुबह ६ से रात १० बजे तक साढ़े ३ इंच बारिश हुई।

जिले की पलसाणा और कामरेज तहसील में पिछले १२ घंटे में हुई २४ इंच बारिश ने शहर की खाड़ियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। पर्वत पटिया में ऋषिकेश विहार सोसायटी के पास मुख्य सड़क पर तीन फीट तक का पानी भरने से लोग परेशान हैं। इसके अलावा आशारटीएम मार्केट के पास मुख्य सड़क पर डेढ़ से दो फीट पानी भर गया। सीमाड़ा बोर्ड ऑफिस के सामने की सड़क पर खाड़ी का पानी भरने आवाजाही बंद करनी पड़ी। कृष्णा नगर और प्रेम नगर के पास खाड़ी का पानी बैक होने से एसएमसी कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। यहां के लोगों के लिए दरगाह के पास, बमरोली और नागसेन नगर (स्कूल-२२१, २५४), वह अन्य स्कूलों में व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ लिंबायत में खाड़ी का पानी बढ़ने से १३ लोगों को कुंभारिया हलपति वास से कुबेरजी विजन कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया गया। प्रमुख पार्क ब्रिज के पास गणेश नगर में जलजमाव से लोगों के लिए आंगनवाड़ी में व्यवस्था की गई है।

डुंभाल टेनामेंट के ओमनगर और लिंबायत के मीठी खाड़ी क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी भर गया है। ओमनगर में रविवार शाम से ही करीब १५० घरों में २ से ३ फीट पानी भरा है। इससे ३०० से अधिक लोग अपने घरों में ताला लगाकर, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घर चल गए हैं। दुकानें बंद होने से जरूरी सामान नहीं मिल पाए। लिंबायत में मीठी खाड़ी क्षेत्र में पानी भरने से करीब ४०० परिवार परेशान हैं। ओम नगर सोसाइटी के प्रमुख इकबाल हमीद पठान (६०) ने बताया कि सोसाइटी में करीब ४९६ फ्लैट हैं। ग्राउंड फ्लोर के करीब १५० में पानी भरा हुआ है। यहां से पानी निकालने के लिए मोटर जेट लगी है, पर बार-बार पानी भर रहा है।

सूरत जिले के पलसाणा ताकुला के बलेश्वर गांव में बत्रीस गंगा खाड़ी उफान पर आ गई है। इसके चलते पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। मंगलवार दोपहर गांव में रहने वाले ४० परिवार बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें बारडोली की फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। गांव से निकाले गए सभी लोगों के लिए बालेश्वर प्राइमरी स्कूल में रहने और खाने की व्यवस्था की गई है।

गुजरात कांग्रेस ने केन्द्रीय बजट को बताया पूरी तरह निराशाजनक

अहमदाबाद (ईएमएस) आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि देश में मंदी और कठिनाइयों से जूझ रहे देशवासियों को बजट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। गुजरात के लिए किसी तरह की कोई राहत, घोषणा या बात नहीं हैं सही मायने में यह बजट चंद शब्दों का श्रृंगार हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने सरकार को दबाई इसलिए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ ही घोषणाएं करनी पड़ीं और अन्य के लिए कुछ भी नहीं। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनावी घोषणापत्र में कह रही थी कि वह वेतन से टैक्स भरने वाले लोगों को 10 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट देगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बजट में किसानों, मजदूरों, मनरेगा के लिए कोई घोषणा या बात नहीं हैं बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्वास्थ्य पर चर्चा की जाएं प्लैटिनम पर सीमा शुल्क कम किया गया और प्लास्टिक पर कर बढ़ाया गया। इस देश में कितने प्लैटिनम खरीदार, कितना उपयोग है? जबकि भारत में हर घर में प्लास्टिक उपयोगकर्ता पाए जाते हैं। उनके बजट में छोटे उद्यमियों और बंद हो रहे एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। सरकार विदेश से आने वाली कंपनियों के टैक्स कम करने की बात करती हैं विदेशों से इतना प्यार, लेकिन देश के जरूरतमंद लोगों की चिंता क्यों नहीं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद बजट में किसानों के लिए कोई ठोस बात नहीं हैं सरकार को असम, बिहार और आंध्र प्रदेश में बाढ़ से नुकसान दिखता है, लेकिन गुजरात के घेड़, पोरबंदर शहर, जूनागढ़, द्वारका और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में भारी बारिश से किसान परेशान हैं, लोग परेशान हैं, यह नहीं दिखाई देता लगातार बारिश से तबाह होने वाले गुजरात के इलाकों के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं की गई हैं इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आम गुजराती या हिंदुस्तानी को खुश कर दें शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की योजना बनाई और पहली नौकरी पक्की स्टाइपेन्ड की घोषणा चुनाव मिनिफेस्टो में की थी, उसे कॉपी करके बजट में चिपका दिया गया, लेकिन वह भी नाममात्र की राशि और नियम व शर्तों के साथ, लालच देनेवाले विज्ञापन की तरह कोई लाभ ना हो और ठगे जाने का अहसास दिलाता हैं देश की जनता महंगाई की मार झेलेगी, नौकरीपेशा लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। जो युवा रोजगार चाहते हैं उनके लिए यह सरकार नौकरी के नाम पर छलावा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस बजट से छोटे उद्यमियों, किसानों और मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिलेगा सिर्फ और महंगाई बढ़ेगी।

प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की सुरक्षा के लिए राज्य प्रशासन तैयार : मुख्यमंत्री

- भूपेन्द्र पटेल ने देवभूमि द्वारका जिले में वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया

गांधीनगर (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सौराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी वर्षा से पैदा हुए हालात की जानकारी जुटाने के लिए मंगलवार को प्रभावित जिलों, विशेषकर जामनगर और देवभूमि द्वारका जिले के गांवों का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने देवभूमि द्वारका और जामनगर जिले के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिला प्रशासन को भारी वर्षा की स्थिति में लोगों की सुरक्षा के लिए जीरो कैजुअल्टी के दृष्टिकोण के साथ काम करने का मार्गदर्शन दिया। देवभूमि द्वारका, जामनगर और पोरबंदर सहित सौराष्ट्र के तटीय जिलों में पिछले पांच दिनों से जारी भारी वर्षा के संदर्भ में निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित होने के कारण मुख्यमंत्री ने देवभूमि द्वारका की तटीय पट्टी और प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देवभूमि द्वारका जिले के कुरंगा गांव में जिले के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में जिले में वर्षा की स्थिति और प्रशासन द्वारा उठाए गए राहत एवं बचाव के कदमों की जानकारी हासिल की। उन्होंने स्थानांतरित किए गए लोगों को सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव सहित अन्य कार्यों में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए सुसज्जित है। मुख्यमंत्री ने द्वारका, कल्याणपुर सहित असाधारण वर्षा वाले क्षेत्रों में उठाए गए कदमों और आगामी दिनों में माल-समान को अधिक नुकसान से बचाने के लिए प्रशासन की तैयारी और समग्र स्थिति का जायजा लेकर लोगों को यह एहसास दिलाने का सुझाव दिया कि राज्य सरकार प्रभावितों के साथ है। उन्होंने संबंधित विभागों को इन क्षेत्रों में पानी उतरते ही आवश्यक सर्वे करने के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया। कलेक्टर जी.टी. पंडया ने समग्र स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि देवभूमि द्वारका जिले में पिछले 30 वर्षों की औसत वर्षा 769 मिमी है, जिसकी तुलना में पिछले पांच-छह दिनों में 980 मिमी औसत वर्षा हुई है। इस प्रकार जिले में 31 इंच औसत वर्षा के समक्ष पिछले 5-6 दिनों में ही 50 इंच वर्षा हुई है। लगातार वर्षा की स्थिति में अग्रिम आयोजन और तत्काल उपाय के कारण पानी में फंसे 23 लोगों को सुरक्षित बाहर लाया गया है। प्रभावितों को शेल्टर हाउस में भोजन और स्वास्थ्य सहित हर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जिले में जहां कहीं भी सड़क एवं परिवहन सेवा प्रभावित हुई हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री की बैठक में मुख्य सचिव राज कुमार, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव पंकज जोशी, पुलिस महानिदेशक विकास सहाय, रेंज आईजी अशोक कुमार यादव, जिला विकास अधिकारी एस.डी. धानाणी, पुलिस अधीक्षक नितेश पांडेय सहित विधायक पबुभा माणेक, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रचनाबेन मोटाणी सहित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के ऑनलाइन निवारण का 'स्वागत' कार्यक्रम 25 जुलाई को होगा

गांधीनगर 23 जुलाई : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष राज्य के नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के ऑनलाइन निवारण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) गुरुवार, 25 जुलाई दोपहर को आयोजित होगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 2003 में शुरू हुए स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत हर महीने के चौथे गुरुवार को राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में जुलाई-2024 का राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम 25 जुलाई को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल गुरुवार, 25 जुलाई दोपहर 3.30 बजे राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और नागरिकों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुनेंगे।

इस 'स्वागत' कार्यक्रम के लिए सामान्य नागरिक-आवेदक अपना अभ्यावेदन गुरुवार, 25 जुलाई की सुबह 8 से 11 बजे के दौरान मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई, स्वर्णिम संकुल-2, गांधीनगर में प्रत्यक्ष रूप से आकर दे सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल दोपहर 3.30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय की जनसंपर्क इकाई में उपस्थित रहकर लोगों की शिकायतें सुनेंगे।

भारी बारिश की संभावना के चलते सूरत की स्कूलों में आज छुट्टी

सूरत (ईएमएस) दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ हैं आगामी दिनों में भारी से अतिभारी बारिश का मौसम विभाग का पूर्वानुमान हैं दक्षिण गुजरात के सूरत शहर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने परिपत्र जारी कर बुधवार को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया हैं सूरत की प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बुधवार छुट्टी रहेगी बुधवार को भी सूरत में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे देखते हुए शिक्षा अधिकारी ने यह फैसला किया हैं सूरत में हो रही भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं जिसमें भटार, पलसाणा, वेसू, पूणा कुंभारिया, सरथाणा, इत्यादि इलाके शामिल हैं जलभराव में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया गया हैं

अहमदाबाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की पहल

अहमदाबाद, २३ जुलाई। अहमदाबाद में बच्चों महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा में सुधार के लिए गुजरात सरकार ने नया कदम उठाया है। शहर के २०५ क्षेत्रों में आपातकालीन कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। यह निर्भया सेफ सिटी परियोजना के तहत एक पहल है। लोग इमरजेंसी में कॉल बॉक्स में लगे बटन को दबा सकते हैं इसके बाद तुरंत पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंच जाएगी।

गुजरात में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की गई है। बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद के कई इलाकों में आपातकालीन कॉल बॉक्स स्थापित किए गए। अहमदाबाद के विशेष पुलिस आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने इसको लेकर जानकारी दी है,

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भूटान नरेश तथा प्रधानमंत्री के सम्मान में स्नेह भोज का आयोजन किया

गांधीनगर 23 जुलाई, 2024 : गुजरात की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान अहमदाबाद पधारे भूटान नरेश श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक तथा प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोबगे के सम्मान में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्नेह भोज का आयोजन किया।

श्री पटेल तथा भूटान नरेश व प्रधानमंत्री ने इस भोज बैठक के दौरान हुई बातचीत में गुजरात-भूटान के बीच आपसी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को अधिक प्रगाढ़ बनाने पर विचार-विमर्श किया। प्रोटोकॉल राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा, मुख्य सचिव श्री राज कुमार तथा वरिष्ठ सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने भूटान नरेश व प्रधान मंत्री को कच्छ की समृद्ध एवं विश्व विख्यात परंपरागत हस्तकला कारीगरी 'रोगान' कला की प्रतिकृति एवं भुजोडी शॉल गुजरात यात्रा की स्मृति के रूप में भेंट की।

गुजरात में सितम्बर तक रोपे जाएंगे १२.२० करोड़ पौधे : भूपेन्द्र पटेल

गांधीनगर, २३ जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर में एक पेड मां के नाम अभियान को अंतिम रूप देने को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के गुजरात में सितम्बर तक १२.२० करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। अहमदाबाद में १०० दिन में ३० लाख पौधे लगाने का लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर में एक पेड मां के नाम अभियान को अंतिम रूप देने को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरित 'एक पेड़ मां के नाम ' अभियान के तहत आगामी सितम्बर माह तक गुजरात में १२.२० करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। अहमदाबाद महानगरपालिका की ओर से मिशन थ्री मिलियन ट्री के अंतर्गत १०० दिन में ३० लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में इस अभियान को अंतिम रूप दे दिया गया है। वन विभाग आगामी वन महोत्सव के अंतर्गत तहसील और गांव स्तर पर इस अभियान को शुरू करेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में पौधरोपण के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। जिसमें कहा गया है कि सितम्बर तक १२.२० करोड़ और मार्च तक राज्यभर में १७ करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा गया है कि भारत सरकार के मेरी लाइफ पोर्टल पर देशभर में रोपे गए पौधों की जानकारी दी गई है, जिसमें गुजरात के ३३ जिलों में चार करोड़ ३ लाख ३३ हजार पौधे लगाए गए हैं। इस मामले में गुजरात देश में दूसरा सबसे अधिक पौधे रोपने वाला राज्य है। बैठक में कहा गया है कि ७५वें वन महोत्सव के दौरान 'एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत तहसील और गांव स्तर पर १०.५० करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे।

अहमदाबाद महानगरपालिका क्षेत्र में १०० दिनों में ३० लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इन पौधों के रोपे जाने से हरियाली का आवरण छह से आठ फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है। शहर में बगीचों, तालाब व मनपा संचालित पार्टी प्लॉट और अन्य जगहों पर पौधरोपण किए जाएंगे।

जैविक कृषि के क्षेत्र में गुजरात पूरे भारत के लिए एक मॉडल राज्य बनेगा : राज्यपाल

- केंद्रीय बजट में प्राकृतिक कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता : किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

- पीएम मोदी ने जैविक कृषि को प्राथमिकता देकर पर्यावरण, प्रकृति और मानव जाति की चिंता की है

गांधीनगर (ईएमएस) गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र के साथ-साथ प्राकृतिक कृषि को प्राथमिकता देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जैविक कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए पर्यावरण, प्रकृति एवं सम्पूर्ण मानव जाति की चिंता की है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए चौगुनी समृद्धि और मजबूत विकास के लिए भारत सरकार की नौ प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र में बदलाव के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि को भी शामिल किया। प्राकृतिक कृषि को भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में भारत में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैविक कृषि उत्पादों की प्रमाणन प्रक्रिया और ब्रांडिंग में भी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों और विज्ञान केंद्रों-विज्ञान संस्थानों की मदद ली जाएगी। इस अवसर पर आचार्य देवव्रत जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया गया। आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में पूरे भारत के लिए एक मॉडल राज्य बनने जा रहा है। मैं इस समय गुजरात में प्राकृतिक कृषि को विशेष प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात में जैविक खेती करने वाले 9.50 लाख से अधिक किसानों को भी बधाई दी।

१३ नए मामले और पांच की मौत; अब तक ३२ ने गंवाई जान

अहमदाबाद, २३ जुलाई। गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने स्वास्थ्य विभाग की धड़कनें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में अब तक इसके ८४ मामले सामने आ चुके हैं। वहीं ३२ ने जान गंवाई है। पड़ोसी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने शुरू कर दी है। चांदीपुरा वायरस के लक्षण फ्लू की तरह होते हैं। अधिकांश यह वायरस १५ साल तक के बच्चों में फैलता है।

गुजरात में चांदीपुरा वायरस के १३ नए मामले सामने आए और पांच की मौत हो गई। हालांकि इनमे से किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि चांदीपुरा वायरस के लक्षण वाले मरीजों के सैंपल को जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआइवी) भेजा गया है।

गुजरात में अब तक चांदीपुरा वायरस के लक्षण वाले मामलों की संख्या ८४ और इससे मरने वालों की संख्या ३२ हो गई है। चांदीपुरा वायरस के लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। यह वायरस मच्छरों, मक्खियों, कीट-पतंगों से फैलता है। १९६६ में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुर गांव में अचानक १५ साल तक के बच्चों की मौत होने लगी थी।

गुजरात के 31 जलाशय हाईअलर्ट पर, नर्मदा बांध में 55 प्रतिशत से अधिक जल भंडारण

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में लगातार हो रही बारिश के चलते 31 जलाशय पूर्ण रूप से छलक जाने से हाईअलर्ट जारी किया गया हैं गुजरात की जीवनदायिनी सरदार सरोवर नर्मदा योजना में जल भंडारण 55 प्रतिशत के पार हो गया हैं फिलहाल नर्मदा बांध में 183724 एमसीएफटी अर्थात कुल संग्रह क्षमता का 55 प्रतिशत से अधिक जल भंडार हुआ हैं जबकि राज्य के अन्य 206 जलाशयों में 223685 एमसीएफटी अर्थात कुल संग्रह क्षमता का 39.93 प्रतिशत जल भंडारण हुआ हैं जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में हो रही बारिश के चलते आज सुबह 8 बजे तक दमणगंगा में 51786 क्यूसेक, उकाई में 31206 क्यूसेक राणा खीरसरा में 23656 क्यूसेक, वेणु-2 में 18960 क्यूसेक, उमियासागर में 18468 क्यूसेक, ओजत-विअर (वंथली) में 16024 क्यूसेक, ओजत-वियर में 15256 क्यूसेक और सरदार सरोवर बांध में 13419 क्यूसेक पानी की आय हुई हैं राज्य के 31 जलाशयों के संपूर्ण रूप से भर जाने से हाई अलर्ट पर रखा गया हैं जबकि 70 से 100 प्रतिशत तक भरे 29 जलाशयों पर अलर्ट जारी किया गया हैं इसके अलावा सरदार सरोवर नर्मदा बांध समेत 50 से 70 फीसदी भरे जलाशयों को चेतावनी जारी किया गया राज्य के 19 बांध 25 से 50 प्रतिशत भरे हैं मंडलवार जलाशयों के जल भंडारण के आंकड़ों पर नजर डालें तो सौराष्ट्र के 141 डैमों में 46.40 प्रतिशत, दक्षिण गुजरात के 13 डैमों में 42.55 प्रतिशत, मध्य गुजरात के 17 डैमों में 35.50 प्रतिशत, कच्छ के 20 डैमों में 32.36 और उत्तर गुजरात के 15 जलाशयों में 26.50 फीसदी जल भंडारण हुआ हैं

विकसित भारत के निर्माण की स्पष्ट राह बनाने वाला सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बजट है: मुख्यमंत्री

गांधीनगर (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्र सरकार के 2024-25 के बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट विकसित भारत के निर्माण की स्पष्ट राह बनाने वाला सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बजट है। इतना ही नहीं, यह बजट जनता-जनार्दन द्वारा लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में व्यक्त किए गए विश्वास का प्रतिबिंब प्रस्तुत करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री की 'ग्यान' यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास पर आधारित विकास की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता झलकती है। इसके साथ ही, रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक कृषि सहित कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश की आजादी के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 तक भारत के युवाओं को विश्व पटल पर यूथ पॉवर के रूप में उभारने की योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया है। युवा शक्ति के कौशल में निखार लाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आगामी वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पांच नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। इन योजनाओं से देश की युवा शक्ति को रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में नए सोपान गढ़ने की एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विकसित भारत के लिए तय की गई 9 प्राथमिकताओं को गति देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि कृषि में उत्पादकता और समर्थन, रोजगार और कुशलता, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, उत्पादन और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा आने वाली पीढ़ी के लिए सुविधाओं जैसी बातों को बजट में शामिल करने का प्रयोग स्वागत योग्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पांच वर्ष में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में जोड़ने की पहल से गुजरात में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बड़ी मदद मिलेगी, साथ ही अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती में जोड़ने का प्रधानमंत्री का संकल्प साकार होगा। इतना ही नहीं, सर्टिफिकेशन और ब्रांड सपोर्ट के साथ प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को मदद करने का प्रधानमंत्री का किसान कल्याण दृष्टिकोण भी इस बजट में प्रतिबिंबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' मंत्र को देश भर में आसानी से साकार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति लागू करने के निर्णय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फास्ट ट्रैक पर लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने रोजगार और प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की 3 योजनाएं शुरू करने की बात का स्वागत करते हुए कहा कि 'जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्कीम' के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नए रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को लाभ मिलेगा तथा गुजरात में युवाओं और युवा उद्यमियों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि औद्योगिक इकाइयों के साथ साझेदारी में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना से महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए खास कौशल कार्यक्रम और प्रमोशन ऑफ मार्केट एक्सेस यानी बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की संभावनाएं गुजरात में वुमन वर्कफोर्स को और अधिक प्रभावी बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण का स्वागत करते हुए कहा कि स्किलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य सरकार और उद्योग के साथ साझेदारी में केंद्र सरकार अगले पांच वर्ष में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का व्यापक स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस बजट में की गई इस घोषणा की भी सराहना की कि 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। इसके फलस्वरूप गुजरात के युवाओं के लिए अपस्किलिंग और स्किल डेवलपमेंट के नए अवसर खुलेंगे।

पीएम आवास योजना के अंतर्गत देश में 3 करोड़ नए आवासों के निर्माण के लिए व्यवस्था करने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप देश के करोड़ों गरीबों को खुद का घर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री के आदिवासी विकास के संकल्प का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के लाभ के सैचुरेशन में तेजी लाई जाएगी। इसका सीधा लाभ 63,000 गांवों के 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लाभार्थियों को मिलेगा। गुजरात के उमरगाम से अंबाजी तक के जनजातीय क्षेत्रों के आदिवासी बंधुओं को भी इसका व्यापक लाभ मिलेगा।

सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आज रेड अलर्ट, मधुबन डैम के १० गेट खोले गए

कच्छ, २३ जुलाई। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से राज्य के कुछ इलाकों में २६ जुलाई तक लगातार ४ दिनों तक भारी से अतिवर्षा की भविष्यवाणी की गई है। आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में रेड अलर्ट दिया गया है। वहीं, कच्छ जिले के नखत्राणा तालुका में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां सड़कों पर नदियों जैसे तेज बहाव से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

गुजरात में अगले सात दिन गरज के साथ भारी से अतिभारी बारिश का पूर्वानुमान

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में खासकर दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा हैं अब उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में भारी बारिश का मौसम विभाग का पूर्वानुमान हैं बता दें कि भारी बारिश से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के ज्यादातर जिले पानी पानी हो गए हैं खासकर सौराष्ट्र में भारी बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया हैं अब बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर और मध्य गुजरात में भारी बारिश की संभावना हैं फिलहाल आधे गुजरात में बरसाती माहौल बरकरार हैं हांलाकि उत्तर और मध्य गुजरात में अब भी अच्छी बारिश की प्रतीक्षा हैं मौसम विभाग के मुताबिक आनेवाले 7 दिनों के दौरान राज्य में गरज के साथ बारिश की संभावना हैं दक्षिण गुजरात और दक्षिण सौराष्ट्र के कुछ हिस्से सौराष्ट्र के अन्य हिस्से मध्य गुजरात पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्से पंचमहल के कुछ हिस्से साबरकांठा के कुछ हिस्से मेहसाणा और आसपास के क्षेत्र सहित उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों और बनासकांठा के कुछ हिस्सों और कच्छ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरानगर हवेली, पोरबंदर, जूनागढ़ और द्वारका बहुत भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट पर हैं जबकि वडोदरा, नर्मदा, भरूच, डांग, तापी, राजकोट, जामनगर, गिर सोमनाथ और कच्छ भारी बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बुधवार 24 जुलाई को नवसारी, सूरत, वलसाड, दमन, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका और दादरानगर हवेली में रेड अलर्ट दिया गया हैं इन जिलों में भारी बारिश हो सकती हैं वडोदरा, छोटाउदेपुर, भरूच, नर्मदा, तापी, डांग, कच्छ और सौराष्ट्र के बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया हैं गुरुवार की बात करें तो नवसारी, डांग, दादरानगर हवेली, दमन में रेड अलर्ट दिया गया हैं इस जिले में भारी बारिश हो सकती हैं वहीं छोटाउदेपुर, भरूच, नर्मदा, तापी में भी बारिश का अनुमान हैं इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ के अन्य जिलों में भी बहुत भारी बारिश का अनुमान हैं शुक्रवार को राज्य के डांग, नवसारी, दमन, दादरानगर हवेली और भावनगर में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, भरूच, चोटाउदेपुर और अमरेली में येलो अलर्ट दिया गया है। वहीं मौसम के जानकार अंबालाल पटेल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की हैं कल सुबह गांधीनगर और अहमदाबाद में बारिश हो सकती हैं दक्षिण सौराष्ट्र के हिस्सों में भारी बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी इसके बावजूद उत्तर सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होगी गुजरातभर में बारिश के हालात बने हुए हैं पिछले 24 घंटों में राज्य की 168 तहसीलों में बारिश हुई हैं जिसमें सबसे ज्यादा बारिश देवभूमि द्वारका में हुई हैं खासकर यहां के कल्याणपुर तालुका में अब तक सबसे ज्यादा बारिश हुई है, यहां 45 इंच बारिश हो चुकी हैं जिससे कल्याणपुर तालुका पानी-पानी हो गया हैं कुछ इलाके संपर्कविहीन हो गये हैं और जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया हैं कल्याणपुर में अब तक 45 इंच बारिश हो चुकी है और कुछ इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए हैं मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आज दोपहर जलमग्न इलाकों का हवाई निरीक्षण किया हैं

बजट से संबंधित प्रतिक्रिया

श्री आशीष कुमार चौहान, एमडी और सीईओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)

''माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में देश में रोजगार सृजन को बहुत बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र भी रोजगार सृजन में भाग ले। साथ ही एंजल टैक्स पर राहत प्रदान करके और मुद्रा ऋण योजना की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करके भारत को नंबर 1 स्टार्टअप राष्ट्र और उद्यमियों का राष्ट्र बनाने का विजन भी नजर आ रहा है। सरकार ने भारत के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिससे कार्यबल में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर देश उनके सहयोग से और तेज गति से आगे बढ़ सकेगा। रोजगार सृजन के एक हिस्से के रूप में कौशल विकास भी उनका एक अनूठा विचार रहा है, जबकि बुनियादी ढांचे के खर्च को बरकरार रखा गया है और राजकोषीय घाटे को 5.1 प्रतिशत की अपेक्षा से 4.9 फीसदी पर कम किया गया है। ये सभी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर ढांचे में बहुत अधिक बदलाव किए बिना हासिल की जा रही हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत की दीर्घकालिक क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा और 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। कुल मिलाकर इस बजट को 10 में से 10 नंबर मिलते हैं!''

मालिक, मुद्रक-प्रकाशक व सम्पादक : लक्ष्मीचन्द जी. अग्रवाल द्वारा ब्रिजाशा ऑफसेट, सरसपुर, अहमदाबाद में मुद्रित करवाकर, स्वेतप्रित बिल्डिंग, खासवाड़ी, बहुचराजी रोड़, वड़ोदरा से प्रकाशित किया। प्रातःकालीन E-mail: janhitaishi@yahoo.co.in Mob.9375504122 R.N.I. 64278/96